लॉस एंजिल्स : पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में बड़ा धमाका, तीन लोगों की मौत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

लोक शक्ति

बंगाल के दुर्गापुर में मोदी से मिलने उमड़ी जनता

RNI Regn. No.7789/1964 | वर्ष-61 > अंक - 206 | रायपुर | शनिवार 19 जुलाई 2025 | विक्रम संवत 2082 | पृष्ठ 8 > मूल्य : 2 रू. | डाक पंजीयन : C.G./RYP DN/71/2023-25

छत्तीसगढ़ शराब घोटाला : भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य को ईडी ने किया गिरफ्तार

कोर्ट ने चैतन्य को 5 दिन की रिमांड पर भेजा

रायपुर । लोकशक्ति

छत्तीसगढ़ में पूर्ववर्ती कांग्रेस शासनकाल में हुए 3200 करोड़ के शराब घोटाले में शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की। ईडी की टीम ने सुबह पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भिलाई स्थित निवास में छापा मारा और कुछ घंटे के भीतर ईडी ने भूपेश के बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार कर रायपुर की विशेष कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें पांच दिन यानि 23 जुलाई की सुबह 11 बजे तक ईडी को रिमांड पर सौंप दिया गया।

ईडी ने भूपेश बघेल के बेटे पर कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को भिलाई स्थित निवास पर छापा मारा था। कुछ घंटे की गहन तलाशी के बाद चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी की गई। बता दें कि चैतन्य बघेल को उनके जन्मदिन के दिन गिरफ्तार किया गया है।

चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के समय कांग्रेस कार्यकर्ता भिलाई में पुलिस से भिड़ गए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिसकर्मियों के साथ झड़प की और ईडी के वाहनों को रोकने की कोशिश की।

यह गिरफ्तारी उस समय हुई जब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ विधानसभा में थे। ईडी की कार्रवाई के विरोध में विधानसभा में कांग्रेस विधायकों ने हंगामा किया। सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए विपक्ष के सदस्यों ने सदन में नारेबाजी की।

ईडी की जांच के अनुसार, यह घोटाला 2019 से 2022 के बीच चला. आरोप है कि सरकारी शराब दुकानों के जरिए नकली होलोग्राम, डुप्लिकेट बोतलों और फर्जी स्टॉक के माध्यम से करीब 2174 करोड़ रुपये की अवैध शराब बेची गई. इस काम को अंजाम देने के लिए एक सिंडिकेट सक्रिय था, जिसमें नेता, अफसर और कारोबारी शामिल थे. शराब की बोतलों पर लगाए जाने वाले होलोग्राम का टेंडर नोएडा की एक अयोग्य कंपनी को दे दिया गया, जो कथित तौर पर एक प्रभावशाली अफसर से जुड़ी थी. इस कंपनी ने नकली होलोग्राम बनाए, जिन्हें ष्टस्स्रुरु के जरिए ठेकों तक भेजा गया. इसके जरिए तीन साल में लगभग 60 लाख पेटियां शराब की अवैध रूप से बिक्री हुई. इस मामले में कांग्रेस नेता और रायपुर के पूर्व मेयर एजाज ढेबर के भाई अनवर ढेबर, आईएएस अनिल टुटेजा और अफसर अरुणपति त्रिपाठी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं।

अमरनाथ यात्रा फिर शुरू, जम्मू से रवाना हुआ 7,908 श्रद्धालुओं का एक और जत्था

एजेंसी। श्रीनगर जम्मू से अमरनाथ यात्रा फिर से शुरू हो गई है। खराब मौसम के कारण यात्रा को एक दिन के लिए रोका गया था। इसके अगले दिन शुक्रवार को जम्मू से 7,908 श्रद्धालुओं का एक नया जत्था अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हुआ। अधिकारियों ने बताया कि 3 जुलाई से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा में अब तक 2.52 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। अधिकारियों ने बताया, शुक्रवार को 7,908 यात्रियों का यह जत्था भगवती नगर यात्री निवास से दो सुरक्षा काफिलों में घाटी के लिए रवाना हुआ। 92 वाहनों का पहला सुरक्षा काफिला 2,879 यात्रियों को लेकर सुबह 3.30 बजे बालटाल कैंप के लिए रवाना हुआ, जबकि 169 वाहनों का दूसरा सुरक्षा काफिला 5,029 यात्रियों को लेकर सुबह 4.25 बजे नुनवान (पहलगाम) कैंप के लिए रवाना हुआ।

बंगाल के दुर्गापुर में पीएम मोदी ने भरी हुंकार, घुसपैठियों को चेताया

घुसपैठियों के खिलाफ होगी कार्रवाई

भाजपा किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने देगी

एजेंसी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में कहा- बंगाल में ञ्जरूष्ट ने अपने स्वार्थ के लिए घुसपैठ को बढ़ावा दिया। इसके लिए इकोसिस्टम बनाया जा रहा है। ये राज्य-देश और बांग्ला संस्कृति के लिए खतरा है।

उन्होंने आगे कहा- TMC ने घुसपैठियों के पक्ष में नई मुहिम शुरू की। मैं साफ कहता हूं- जो भारत का नागरिक नहीं है और घुसपैठ करके आया है, उसपर संविधान के तहत कार्रवाई होकर रहेगी। बंगाल के खिलाफ साजिश को भाजपा कामयाब नहीं होने देगी, ये मोदी की गारंटी है।

मोदी ने दुर्गापुर में 5000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इसमें ऑयल, गैस, बिजली, सड़क और रेल से जुड़ी कई अन्य विकास परियोजनाएं शामिल हैं।

दुर्गापुर बंगाल के पश्चिम वर्धमान जिले का शहर है। राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। 2025 में मोदी की यह दूसरी पश्चिम बंगाल यात्रा है। इससे पहले उन्होंने 29 और 30 मई को अलिपुरद्वार और कूच विहार में परियोजनाओं का शिलान्यास किया था।

आप नेताओं की बढ़ेंगी मुश्किलें, 3 घोटालों के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज, ईडी करेगी जांच

नई दिल्ली। एजेंसी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने पार्टी सरकार के समय हुए तीन बड़े घोटालों की जांच शुरू कर दी है। इन घोटालों में 6368 करोड़ रुपये से ज्यादा की गड़बड़ी का शक है। ईडी ने इन मामलों में केस दर्ज कर लिया है। ये केस अस्पताल बनाने, रैन बसेरा (शेल्टर होम) और सीसीटीवी कैमरे लगाने से जुड़े हैं।

अस्पताल घोटाला 5590 करोड़ रुपये 2018-19 में दिल्ली सरकार ने 24 अस्पताल बनवाने का फैसला लिया था। सरकार ने कहा था कि 6 महीने में अस्पताल बनकर तैयार हो जाएंगे। लेकिन 800 करोड़ रुपये

खर्च हो गए, फिर भी आधा काम भी नहीं हुआ। लोक नायक अस्पताल का खर्च 488 करोड़ से बढ़कर 1135 करोड़ रुपये हो गया। ईडी का आरोप है कि बिना ठीक से मंजूरी लिए काम शुरू कर दिया गया। ईडी जल्द ही AAP के नेताओं से पूछताछ करेगी। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और सौरभ भारद्वाज से सवाल-जवाब हो सकते हैं। सत्येंद्र जैन पहले भी मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल जा चुके हैं, अभी जमानत पर बाहर हैं।

पीएम मोदी ने बिहारवासियों को दी बड़ी सौगात; कहा- बनाएंगे नया बिहार

पीएम मोदी ने 7217 रुपये की योजनाओं की दी सौगात

एजेंसी

पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहारवासियों को 7217 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की सौगात दे दी है। पीएम मोदी ने सड़क और रेल के विकास और इससे जुड़े कई चीजों का तोहफा दिया। पीएम पोदी ने कहा कि आज बिहार में रोड, रेल का खूब विकास हो रहा है।

पैदावार और खेती के मामले में कई जिले पिछड़े हैं

पीएम मोदी ने कहा कि पैदावार और खेती के मामले में कई जिले पिछड़े हैं। धन धान्य योजना के जरिए हमलोग इन पिछड़े जिलों को मदद देंगे। हमलोगों का पूरा फोकस पिछड़ों पर है। उन्होंने कहा

अब सब परिवार को मुफ्त में बिजली उपलब्ध

सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि लोगों को मुफ्त बिजली देने का एलान भी हमलोगों ने कर दिया था। 2005 से बिजली कहां रहती थी। पटना में भी आठ घंटे बिजली रहती थी। अब देखिए हमलोग कितना बिजली दे रहे हैं। हमलोगों ने तय कर लिया है कि अब सब परिवार को मुफ्त में बिजली उपलब्ध करवाना है। आज ही कैबिनेट मीटिंग रखे हैं।

कि आज केंद्र सरकार ने जिन विकास योजनाओं की सौगात दी है, इन सारे प्रयासों का सबसे बड़ा लाभ होगा। बिहार का विकास होगा। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस और राजद गरीबों, दलितों, पिछड़ों और वंचित वर्गों के नाम पर राजनीति करते आए हैं। लेकिन यह लोग अपने परिवार से बाहर किसी को सम्मान नहीं देते। आज इनका हाल पूरा बिहार देख रहा है। हमें बिहार को इनलोगों से दूर रखना है। यह लोग कभी बिहार का विकास कर रही नहीं सकते हैं। इसलिए हमें मिलकर बिहार के विकास को और गति देनी है। हमें संकल्प लेना है कि बनाएंगे नया बिहार, फिर एक बार एनडीए सरकार। इसके बाद पीएम ने भारत माता के जयकारे लगाकर अपना संबोधन खत्म किया।

गोल्डन टेंपल को उड़ाने की धमकी देने वाले 2 गिरफ्तार, तमिलनाडु से पकड़े गए; एसजीपीसी को भेजे थे 5 मेल

अमृतसर अमृतसर के गोल्डन टेंपल को बम से उड़ाने की धमकियों के मामले में सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी सफलता मिली है। इस केस में तमिलनाडु से दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये आरोपी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति को धमकी भरे ई-मेल भेजने के मामले में पकड़े गए हैं। 14 जुलाई से अब तक SGPC को पांच धमकी भरे ई-मेल मिल चुके हैं। मेल में गोल्डन टेंपल को RDX से उड़ाने की बात कही गई थी। इसके बाद अमृतसर में सुरक्षा एजेंसियां तुरंत अलर्ट हो गईं। मंदिर परिसर और आसपास के इलाकों में सख्त सुरक्षा और तलाशी अभियान चलाया गया। पिछले दो दिनों से जांच टीमें तमिलनाडु में सक्रिय थीं। दो संदिग्धों को हिरासत में लिया गया, लेकिन उनकी पहचान अभी सार्वजनिक नहीं की गई है।

महाराष्ट्र के इस्लामपुर का बदलेगा नाम नया नाम होगा ईश्वरपुर, केंद्र सरकार को भेजा

महाराष्ट्र सरकार ने सांगली जिले के इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर करने की शुक्रवार को घोषणा की। यह घोषणा राज्य विधानमंडल के मानसून सत्र के अंतिम दिन की गई। यह कदम हिंदूवादी संगठन शिव प्रतिष्ठान द्वारा सांगली कलेक्टरेट को एक ज्ञापन भेजकर इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर करने की मांग के बाद उठाया गया। शिव प्रतिष्ठान का नेतृत्व संभाजी भिड़े करते हैं, जिनके समर्थकों ने कहा था कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती, वे चैन से नहीं बैठेंगे। इस्लामपुर से शिवसेना के एक नेता ने बताया कि नाम बदलने की मांग 1986 से की जा रही है। फिलहाल, राज्य सरकार ने 'ईश्वरपुर' नाम तय कर लिया है और प्रस्ताव को मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को भेज दिया है

केंद्र सरकार को भेजा प्रस्ताव

मंत्री छगन भुजबल ने विधानसभा को सूचित किया कि पिछले कई वर्षों से सांगली ज़िले के इस्लामपुर शहर का नाम बदलकर 'ईश्वरपुर' करने की मांग उठ रही है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए, राज्य सरकार ने 'ईश्वरपुर' नाम तय कर लिया है और प्रस्ताव को मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को भेज दिया है।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल ने विधानसभा को सूचित किया कि अगर केंद्र सरकार मंजूरी दे देती है, तो इस्लामपुर का आधिकारिक नाम बदलकर ईश्वरपुर कर दिया जाएगा।

देश | भारतीय नौसेना की बढ़ेगी ताकत,

नौसेनो में शामिल होगा देश का पहला स्वदेशी आईएनएस 'निस्तार'

नई दिल्ली एजेंसी। भारतीय नौसेना अपनी स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता में एक बड़ा कदम उठाते हुए शुक्रवार को विशाखापत्तनम के नौसेना डॉकयार्ड में अपनी पहली स्वदेशी निर्मित डाइविंग सपोर्ट वेसल (डीएसवी), आईएनएस निस्तार को कमीशन करेगी।

इस समारोह की अध्यक्षता रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ करेंगे। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस ऐतिहासिक अवसर पर मौजूद रहेंगे। रक्षा मंत्रालय के आधिकारिक एक्स अकाउंट पर शुक्रवार को एक वीडियो शेयर किया गया, जिसमें आईएनएस निस्तार की खूबियों को बताया गया है।

उन्होंने एक्स पर लिखा, निस्तार– भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी डिजाइन किया गया डाइविंग सपोर्ट वेसल आज विशाखापत्तनम में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ द्वारा नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी की उपस्थिति में कमीशन किया जाएगा। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित, इसमें 80 प्रतिशत स्वदेशी सामग्री लगी है और 120 एमएसएमई ने मिलकर बनाया है। निस्तार गहरे समुद्र में गोताखोरी और पनडुब्बी बचाव करने में सक्षम है। 10,500 टन से अधिक वजन वाला यह जहाज कई डेक वाले सैचुरेशन डाइविंग कॉम्प्लेक्स, आरओवी, और डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल्स के लिए मदरशिप के रूप में कार्य करता है।

'निस्तार' नाम संस्कृत से लिया गया है, जिसका अर्थ है मुक्ति, बचाव या उद्धार। यह जहाज पूरी तरह से भारत में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (एतएसएल) द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है, जो भारत की रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

आईएनएस निस्तार में 80 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग हुआ है और इसमें लगभग 120 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की भागीदारी रही है।

अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ सड़क पर उतरे सभी 50 राज्यों के लोग

भारी विद्रोह से ह्वाइट हाउस तक मचा हड़कंप

वाशिंगटन डीसी : एजेंसी।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर में ट्रेड और टैरिफ वार छेड़ने के साथ अपने कई अन्य अजीबोगरीब फैसलों के चलते अपने ही देश में घिर गए हैं। गत 2 दिनों से ट्रंप के खिलाफ अमेरिका के विभिन्न शहरों में जोरदार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अमेरिकी जनता ट्रंप की कई नीतियों के विरोध में सड़क पर उतर आई है। पूरे देश में प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप प्रशासन और उनकी नीतियों के खिलाफ पोस्टर, बैनर और नारों के साथ अपनी असंतुष्टि जाहिर की है।

अमेरिका के 50 राज्यों में हुआ विरोध 'गुड ट्रबल लाइव्स ऑन' नामक विरोध आंदोलन ने देश के सभी 50 राज्यों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। न्यूयॉर्क में प्रदर्शनकारियों को इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट (ICE) भवन के पास एक चौराहे को अवरुद्ध करते हुए देखा गया। एक विरोध प्रदर्शन के दौरान, जब प्रदर्शनकारी एक इमिग्रेशन कोर्ट के बाहर इकट्ठा हुए तो उन्होंने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ 'गुड ट्रबल लाइव्स ऑन' राष्ट्रीय विरोध दिवस के तहत तख्तियां थाम रखी थीं।

इमिग्रेशन भवन के बाहर भी धरना

एक वीडियो में देखा गया कि ट्रंप और इमिग्रेशन (ICE) विरोधी प्रदर्शनकारियों ने न्यूयॉर्क सिटी के मैनहैटन स्थित फेडरल प्लाज़ा में ICE भवन के बाहर एक चौराहे पर बैठकर धरना दिया और रास्ता अवरुद्ध कर दिया।

1600 जगहों पर हुआ प्रदर्शन

ट्रंप के खिलाफ यह प्रदर्शन अटलांटा (जॉर्जिया), सेंट लुइस (मिसौरी), ओकलैंड (कैलिफोर्निया), और एनापोलिस (मैरीलैंड) समेत करीब

1600 जगहों पर हुआ। इसमें ट्रंप प्रशासन की स्वास्थ्य देखभाल में कटौती, इमिग्रेशन नीतियों और अन्य फैसलों की खिलाफत की गई। इसका उद्देश्य दिवंगत कांग्रेस सदस्य और नागरिक अधिकारों के नेता जॉन लुईस को श्रद्धांजलि देना भी था।

'गुड ट्रबल' आंदोलन क्या है?

'गुड ट्रबल' आंदोलन का नाम जॉन लुईस की उस प्रसिद्ध अपील से लिया गया है, जो उन्होंने 2020 में अपनी मौत से पहले अमेरिकी नागरिकों से की थी। उन्होंने कहा था, ÷अच्छी परेशानी में पड़ो, ज़रूरी परेशानी में पड़ो और अमेरिका की आत्मा का उद्धार करो।÷ बता दें कि जॉन लुईस 'बिग सिक्स' नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं के समूह के अंतिम जीवित सदस्य थे, जिसका नेतृत्व डॉ. मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने किया था। लुईस ने हमेशा अहिंसक आंदोलन और न्याय की लड़ाई का समर्थन किया, और यह आंदोलन उनके विचारों की विरासत को आगे बढ़ाता है।

प्रदर्शनकारियों का क्या है कहना? पब्लिक सिटीजन संगठन की सह-अध्यक्ष लीसा गिल्बर्ट ने प्रदर्शन से पहले कहा, हम अपने देश के इतिहास के सबसे भयावह क्षणों में से एक से गुजर रहे हैं। प्रशासन में बढ़ते अधिनायकवाद और अव्यवस्था से हम सभी जूझ रहे हैं... जब हमारे लोकतंत्र के अधिकारों, स्वतंत्रताओं और अपेक्षाओं को चुनौती दी जा रही है।÷ इस राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य ट्रंप प्रशासन की उन नीतियों और कार्यों के खिलाफ आवाज़ उठाना है जिन्हें कई नागरिक मानवाधिकारों के उल्लंघन और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए खतरा मानते हैं।

कनाडा में विमान हाईजैक होने से मचा हड़कंप, NORAD ने पीछे दौड़ाया F-15 फाइटर जेट

एजेंसी। प्लान हाईजैक करने वाला आरोपी कनाडा का ही निवासी है। इसने वैंकूवर हवाई अड्डे पर एक छोटे विमान को हाइजैक कर लिया। रॉयल कनाडाई माउंटेड पुलिस ने बताया कि कासीम पर आतंकवाद से जुड़ी हाइजैकिंग का आरोप लगाया गया है।

यह घटना मंगलवार को हुई। आरसीएमपी के अनुसार कसीम ने विक्टोरिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट (वैंकूवर आइलैंड) पर एक फ्लाइट प्रशिक्षक को धमकी देकर एक सेसना विमान पर कब्जा कर लिया और फिर लगभग 40 मील (64 किलोमीटर) की उड़ान भरते हुए वैंकूवर पहुंचे। टैमी लॉब ने कहा, ÷जांचकर्ताओं ने पाया है कि संदिग्ध ने वायुमंडल में व्यवधान डालने के लिए वैचारिक प्रेरणा के साथ यह कदम उठाया।÷

हाईजैकर ने खुद को कहा अल्लाह का दूत कहा जा रहा है कि हाईजैकर ने खुद को अल्लाह का दूत÷ और ÷मसीहा÷ बताया, दावा किया कि उसे मानवता को जलवायु परिवर्तन से बचाने के लिए भेजा गया है। उसने कहा कि ÷ फरिश्ता जिब्राइल मेरे सामने आए और अल्लाह का संदेश दिया।÷ कासीम ने सोशल मीडिया पर लिखी पोस्ट में कहा ÷अचानक और तेजी से बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग÷ के कारण इंसानों के कुछ वर्षों में विलुप्त हो जाने की चेतावनी दी गई थी।

लोकशक्ति
www.lokshakti.in

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने 24,550 समूहों को 147 करोड़ की राशि वितरित

0 सामुदायिक निवेश कोष में कोरिया और राजनांदगांव जिला ने महिला समूहों को प्रदान किया शत-प्रतिशत राशि

रायपुर, । राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) योजना के माध्यम से राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के महिलाओं को छोटे-छोटे व्यवसायिक गतिविधियों से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने हर सभंव प्रयास किया जा रहा है।

बिहान के अंतर्गत सामुदायिक निवेश कोष (सीआईएफ) में इस वित्तीय वर्ष में अब तक राज्य के 24 हजार 550 महिला स्व-सहायता समूहों को 147 करोड़ 30 लाख रूपए किए गए है। इसमें से कोरिया और राजनांदगांव जिला द्वारा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। इन जिलों में लक्षित शत-प्रतिशत समूह को राशि प्रदान कर दी गई है।

गौरतलब है कि सामुदायिक निवेश कोष के तहत इस वित्तीय वर्ष में 42 हजार 275 स्व-सहायता समूहों की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 253 करोड़ 65 लाख रूपए की सहायता पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इस तरह लक्ष्य के करीब 58 प्रतिशत की प्राप्ति की जा चुकी है। राज्य में सात जिले ऐसे है जिन्होंने मात्र चार माह की अवधि में 70 प्रतिशत से अधिक की उपलब्धि हासिल कर महिलाओं को लाभान्वित किया है। इसमें से कोरिया जिले की शत-प्रतिशत लक्षित 425 महिला स्व-सहायता समूहों को 60 हजार रूपए प्रति समूह की दर से कुल 2.55 करोड़ तथा राजनांदगांव जिले की भी शत-प्रतिशत लक्षित 628 स्व-सहायता समूहों को 3 करोड़ 76 हजार रूपए की राशि प्रदान की गई है।

इसी प्रकार दंतेवाड़ा जिला में 400 स्व-सहायता समूहों को 2 करोड़ 40 लाख वितरित कर 93 प्रतिशत, सरगुजा में 300 समूहों को 1 करोड़ 80 लाख वितरित कर 90 प्रतिशत, बलौदाबाजार में 2020 समूहों को 12 करोड़ 12 लाख रूपए वितरित कर 86 प्रतिशत, बलरामपुर-रामानुजगंज जिला में 800 समूहों को 4 करोड़ 80 लाख रूपए वितरित कर 77 प्रतिशत और गरियाबंद जिला में 900 स्व सहायता समूहों को 5 करोड़ 40 लाख रूपए वितरित कर 70 प्रतिशत का वितरण किया जा चुका है। उल्लेखनीय है कि अधिकतर महिला समूह कृषि कार्यों से जुड़े हैं और जून-जुलाई के दौरान उन्हें बीज, खाद, मजदूरी के लिए धन की आवश्यकता होती है। इस राशि के मिलने से उन्हें अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने में काफी मदद मिली है।

मुख्यमंत्री ने फील्ड हेल्थ वर्कफोर्स के लिए 151 नई गाड़ियों को दिखाई हरी झंडी

रायपुर, लोकशक्ति। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों तक सुलभ और प्रभावी स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए आज एक ऐतिहासिक कदम उठाया। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज अपने निवास से फील्ड स्तर के स्वास्थ्यकर्मियों के लिए 151 नई गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये वाहन बस्तर और सरगुजा जैसे दुर्गम क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा, यह पहल एक स्वस्थ छत्तीसगढ़ की दिशा में मजबूत कदम है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पुराने और खराब वाहनों को हटाकर अत्याधुनिक गाड़ियों को शामिल किया गया है, जिससे राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के क्रियान्वयन, निगरानी और पर्यवेक्षण में तेजी आएगी। उन्होंने बताया कि ये वाहन जिला और ब्लॉक स्तर के अधिकारियों और फील्ड हेल्थ स्टाफ को दिए जाएंगे, जिससे नियमित निरीक्षण, स्वास्थ्य शिविरों की प्रभावी निगरानी, दूरदराज़ इलाकों में त्वरित पहुंच और आपातकालीन स्थितियों में तुरंत प्रतिक्रिया संभव हो सकेगी। इससे राज्य की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली अधिक सक्रिय, प्रभावी और उत्तरदायी बनेगी।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि इन वाहनों का वितरण सभी जिलों में चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा और पहले चरण में ये 12 जिलों में बस्तर और सरगुजा संभागों को भेजे जा रहे हैं। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि राज्य में शीघ्र ही 851 नई एंबुलेंस सेवाएं शुरू की जाएंगी, जिनमें 108 इमरजेंसी सेवा के लिए 375 एंबुलेंस, ग्रामीण मोबाइल चिकित्सा इकाइयों के लिए 30 एंबुलेंस, और मुफ्त 'मुक्तांजलि' शव वाहन सेवा के लिए 163 गाड़ियाँ शामिल हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनजातीय समुदायों के कल्याण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि पीएम जन मन योजना के अंतर्गत विशेष रूप से 30 एंबुलेंसों की व्यवस्था की जा रही है।

राज्यपाल ने 2024-25 के लिए भावना बोहरा को उत्कृष्ट विधायक सम्मान से सम्मानित किया

रायपुर, लोकशक्ति

छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र 2024-25 के अंतिम दिन विधानसभा अध्यक्ष डॉ.रमन सिंह जी ने उत्कृष्ट विधायकों की घोषणा करते हुए पंडरिया विधायक भावना बोहरा को वर्ष 2024-25 के उत्कृष्ट विधायक के रूप में उनके नाम की घोषणा की। भावना बोहरा ने वर्ष 2024-25 की अवधि में संपन्न हुए बजट सत्र, मानसून सत्र एवं शीतकालीन सत्र में विधानसभा में विभिन्न विषयों पर चर्चा के दौरान सक्रियता से भाग लिया, वहीं क्षेत्र एवं प्रदेश से जुड़ें प्रमुख मुद्दों और जनता के हित को ध्यान में रखते हुए उनकी समस्याओं के समाधान व आवश्यकताओं को लेकर मुखर रही। भावना बोहरा ने पंडरिया विधानसभा सहित प्रदेश में संचालित हो रहे विकास कार्यों और योजनाओं के साथ-साथ सरकार का पक्ष भी रखा।

वे लगातार विधानसभा में उपस्थित रहीं एवं सदन की गतिविधियों में सक्रियता से भाग लिया। मानसून सत्र में भी उनके द्वारा लगातार क्षेत्र व प्रदेश से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों एवं महिला, युवा, उद्योग,शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे विभिन्न विषयों से जुड़ें प्रश्न सदन में किए। 16 जुलाई 2025 को विधानसभा परिसर स्थित सेंट्रल हॉल के समक्ष आयोजित उत्कृष्टता अलंकरण समारोह में छत्तीसगढ़ के महामहिम राज्यपाल रमेन डेका जी द्वारा पंडरिया विधायक को प्रतीक चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र भेंट कर पंडरिया विधायक भावना बोहरा को उत्कृष्ट विधायक सम्मान से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय विधानसभा अध्यक्ष डॉ.रमन सिंह जी, अतिविशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय मुख्यमंत्री माननीय विष्णु देव साय जी, नेता प्रतिपक्ष चरणदस महंत जी, संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप जी,समस्त मंत्रीगण, विधानसभा सदस्य उपस्थित रहे।

इस अवसर पर महामहिम राज्यपाल माननीय रमेन डेका जी ने कहा कि उत्कृष्ट विधायक के लिए चयनित श्रीमती भावना बोहरा जी को हार्दिक बधाई देता हूँ आपने जनहित,संसदीय गरिमा के लिए जो योगदान दिया है यह निश्चित ही प्रेरणादायी है। आप पहली बार विधानसभा सदस्य के रूप में चुनकर आईं हैं और उत्कृष्ट विधायक का आपको सम्मान मिला यह बहुत ही गौरव की बात है। माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने कहा कि उत्कृष्ट विधायक का सम्मान मिलने पर मैं भावना बोहरा को बधाई देता हूँ जो पहली बार जीतकर आईं और विधानसभा की कार्यवाही में सक्रियता से हिस्सा लिया, क्षेत्र के मुद्दों और जनता की बातों को सदन में मुखरता से रखा। माननीय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी ने कहा कि मैं पंडरिया विधायक भावना बोहरा जी को इस सम्मान के लिए बधाई देता हूँ।

आप निरंतर इसी प्रकार जनता के हितों के प्रति अपने दायित्वों को पूरा करती रहें और विधानसभा में आपकी सक्रियता ऐसे ही बनी रहे मेरी शुभकामनाएं है। नेता प्रतिपक्ष चरणदस महंत जी ने कहा कि श्रीमती भावना बोहरा जी को उत्कृष्ट विधायक का सम्मान मिलने पर मैं बधाई देता हूँ। संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप जी ने भी भावना बोहरा जी के कार्यों, विधानसभा की कार्यवाही में सतत उपस्थिति,सक्रियता और जनहित के विषयों को सदन के पटल पर रखने हेतु उनकी तत्परता की सराहना करते हुए उत्कृष्ट विधायक का सम्मान मिलने पर उन्हें शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने महामहिम राज्यपाल रमेन डेका जी, विधानसभा अध्यक्ष माननीय डॉ.रमन सिंह जी, मुख्यमंत्री माननीय विष्णु देव साय जी, संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप जी, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी एवं समस्त सदस्यों, और विधानसभा के प्रत्येक अधिकारी व कर्मचारी तथा विशेष रूप से पंडरिया विधानसभा की जनता के प्रति आभार एवं कृतज्ञता व्यक्त की।

उन्होंने कहा कि पंडरिया विधानसभा की उत्कृष्ट जनता के आशीर्वाद,सहयोग एवं मार्गदर्शन से मुझे यह सम्मान मिला है जिसे मैं पंडरिया विधानसभा के प्रत्येक नागरिक को समर्पित करती हूँ। एक जनप्रतिनिधि के रूप में यह सम्मान मिलना मेरे लिए जितना गर्व की बात है उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी है। यह सम्मान मुझे और भी प्रेरित करेगा अपने दायित्वों को पूरा करने एवं पंडरिया विधानसभा की जनता ने जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी है उन्हें उनकी आकाँक्षाओं अनुरूप पूरा करने हेतु उर्जा प्रदान करेगी। इस सम्मान के प्रति मैं निरन्तर अपने दायित्वों को पूरा करती रहूँ जिसके लिए मैं आश्वस्त करती हूँ कि जब भी मुझे अवसर मिलेगा पूरी तत्परता से क्षेत्र एवं प्रदेश से जुड़े मुद्दों, जनहित के विषयों को सदन के समक्ष रखती रहूंगी। उन्होंने कहा कि विगत डेढ़ वर्ष में माननीय विधानसभा अध्यक्ष डॉ.रमन सिंह जी का संरक्षण व मार्गदर्शन मुझे प्राप्त हुआ इसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी, वरिष्ठजनों द्वारा प्रोत्साहन एवं सदन के सभी सम्मानीय सदस्यों का सहयोग मुझे मिला। विधानसभा की कार्यवाही से मुझे बहुत से अनुभव सिखने को मिले हैं और यह अनुभव मुझे अपने कर्तव्य पथ पर चलने एवं जनता की सेवा और क्षेत्र का विकास करने के लिए हर पथ में मार्ग प्रशस्त करेगा।

अवैध शराब बिक्री करने वाला पकड़ाया

बलौदाबाजार, जिल की चौकी करहीबाजार पुलिस ने अवैध रूप से शराब बेचने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है तथा उसके कब्जे से 32 पाव देशी मसाला शराब जब्त किया है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक श्रीमती भावना गुप्ता के निर्देशन में आमजनों की शिकायत एवं समस्याओं का त्वरित निराकरण करने हेतु जिले में महत्वाकांक्षी योजना समाधान सेल प्रारंभ किया गया है, जिसकी सहायता से किसी भी प्रकार की सूचना, शिकायत अथवा आपराधिक गतिविधि की जानकारी समाधान सेल हेल्पलाइन नंबर 94792 20392 में व्हाट्सएप अथवा कॉल के जरिए प्रदान की जा सकती है।

छ. ग. कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने विभिन्न मांगों को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा

भोपालपटनम, 1छ. ग. कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ब्लॉक भोपालपटनम कर्मचारियों ने क्लब प्रांगण से तहसील कार्यालय तक रैली के रूप में जाकर मुख्यमंत्री एवं सचिव के नाम विभिन्न मांगों को लेकर तहसीलदार भोपालपटनम को ज्ञापन सौंपा। इनमें प्रमुख मांगेङ्क प्रदेश के कर्मचारियों एवं पेंशनरों के लिए मोदी की गारंटी अनुसार केन्द्र के समान 2 प्रतिशत महंगाई भत्ता, प्रदेश के कर्मचारियों के लिए मोदी की गारंटी अनुसार जुलाई 2019 से समय-समय पर देय महंगाई भत्ते की लंबित एरियर्स राशि का समायोजन जीपीएफखाते में किया जाने, वेतन विसंगति एवं अन्य मुद्दो के लिए गठित पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक किया जावे, प्रदेश में चार स्तरीय पदोन्नत समयमान वेतनमान कमशः 8 वर्ष, 16 वर्ष, 24 वर्ष एवं 30 वर्ष सेवा पूर्ण करने उपरांत लागू करना, सहायक शिक्षक पद पर नियुक्त शिक्षक एवं सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी को तृतीय समयमान वेतनमान स्वीकृति आदेश जारी किया जावे, प्रदेश में अन्य भाजपा शासित राज्यों की भांति कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू की जावे, प्रदेश में अनुकंपा नियुक्ति निःशर्त लागू करने स्थायी आदेश जारी किया जाये। वर्तमान में 10 प्रतिशत सीलिंग समाप्त करते हुए सीधी भर्ती के समस्त पदों पर अनुकंपा नियुक्ति दी जावे, मध्यप्रदेश की भांति छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय सेवकों को 300 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण दिया जावे।

33वीं नेशनल कराते चैम्पियनशिप का त्रिदिवसीय आयोजन 17 अगस्त से

रायपुर, छत्तीसगढ़ कराते संघ द्वारा 33 वीं नेशनल कराते चैम्पियनशिप का आयोजन 17 18 एवं 19 अगस्त को अग्रसेन धाम लाभांडी रायपुर में आयोजित किया गया है। उक्त जानकारी प्रेस विज्ञप्ति जारी कर देते हुए विजय अग्रवाल अध्यक्ष एवं सचिव अजय साहू ने बताया कि इस चैम्पियनशिप प्रतियोगिता में सीनियर जूनियर एवं सब जूनियर वर्ग के संपूर्ण देश से 800 खिलाड़ी एवं अधिकारी भाग लेंगे। 17 अगस्त को खिलाड़ियों का पंजीयन होने के पश्चात रेफरी काउंसिल द्वारा टेक्निकल सेमीनार एवं रेफरी परीक्षा का आयोजन होगा। द्वितीय दिवस 18 अगस्त को सुबह 10 बजे उद्घाटन समारोह के पश्चात सब जूनियर वर्ग की स्पर्धा होगी ।

जवान ने की आत्महत्या, कारण अज्ञात

एजेंसी।जगदलपुर, ।

बस्तर बस्तर जिले के परपा क्षेत्र स्थित सरकारी पुलिस क्वार्टर में एक पुलिस जवान ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मृतक की पहचान संदीप बाकला के रूप में हुई है. फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार, संदीप बाकला का हाल ही में लोहंडीगुड़ा में तबादला हुआ था, लेकिन उसने अभी तक नई पोस्टिंग पर ज्वाइन नहीं किया था। संदीप लंबे समय से ट्रैफिक विभाग में अपनी सेवाएं दे रहा था। बताया जा रहा है कि परिजनों से बातचीत करने के बाद संदीप अपने कमरे में गया था, जहां बाद में उसका शव फंदे पर लटका हुआ मिला।

45 वर्षीय महिला जनपद सदस्य अचानक लापता, परिवार ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत

एजेंसी।कोडागांव, ।

जिले की फरसगांव जनपद पंचायत की सदस्य रैयमती कोर्राम (45 वर्ष) 8 दिन पहले अचानक घर से गायब हो गई। महिला 9 जुलाई की दोपहर लगभग 3:30 बजे बिना किसी को कुछ बताए अपने घर से निकली थीं। उन्होंने बाद में फोन कर कहा था कि वह जिला अस्पताल इलाज के लिए गई हैं, लेकिन तब से उनका कोई पता नहीं चल सका है और उनका मोबाइल नंबर भी बंद है। रैयमती के पति ने फरसगांव थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि रैयमती ने उस दिन लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी और उनके साथ एक बैग था जिसमें कपड़े रखे थे। महिला के गले में सोने का मंगलसूत्र, कानों में सोने के टॉप्स और नाक में सोने की फूली थी। उनका कद लगभग 5 फुट और रंग सांवला है। वे हिंदी, हल्बी और छत्तीसगढ़ी भाषाएँ बोल सकती हैं। परिवार ने महिला के घर न लौटने पर जिला अस्पताल और रिश्तेदारों से जानकारी लेने के बावजूद कोई सुराग नहीं पाया। पुलिस भी मामले की जांच में लगी है। परिवार ने आम जनता से अपील की है कि यदि रैयमती कोर्राम के बारे में कोई जानकारी हो तो निकटतम पुलिस थाने को सूचित करें।

कोण्डागांव की बालिका ने ताईवान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल जीतकर रचा इतिहास - मुख्यमंत्री

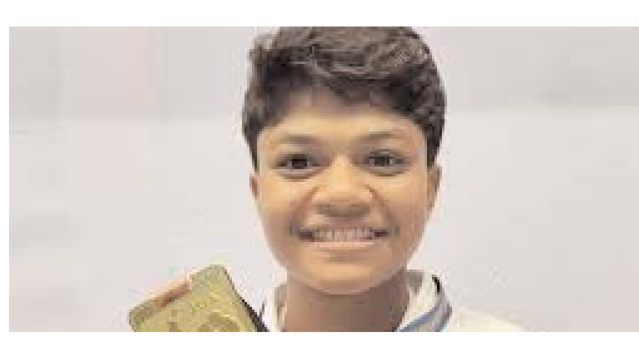

रायपुर, ।छत्तीसगढ़ के कोण्डागांव जिले की बालिका रंजीता कोरेटी ने ताइपे (ताईवान) में आयोजित एशियन कैडेट जूडो चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद बालगृह बालिका कोण्डागांव की रंजीता ने कई देशों के खिलाड़ियों को पराजित करते हुए यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इस गौरवशाली उपलब्धि पर रंजीता को हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि यह न केवल कोण्डागांव जिले बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के लिए अत्यंत गर्व का क्षण है। उन्होंने कहा कि रंजीता जैसी बेटियाँ राज्य की उम्मीद और नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा हैं, जो यह सिद्ध कर रही हैं कि छत्तीसगढ़ की बेटियाँ अब वैश्विक मंच पर अपनी अलग पहचान बना रही हैं।

रंजीता की इस उपलब्धि के पीछे जिला बाल संरक्षण इकाई, महिला एवं बाल विकास विभाग एवं बालगृह संस्था की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सतत मार्गदर्शन और सहयोग से रंजीता मानसिक और शारीरिक रूप से निरंतर सशक्त होती गई। खेलों में विशेष रुचि और विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखते हुए उसे आईटीबीपी के सहयोग से जूडो का प्रशिक्षण दिलवाया गया। रंजीता ने वर्ष 2021 में चंडीगढ़ में आयोजित ओपन नेशनल जूडो टूर्नामेंट में 40 किलोग्राम वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी खेल यात्रा की प्रभावशाली शुरुआत की।

इसके पश्चात् वर्ष 2022 में भोपाल में आयोजित ओपन नेशनल जूडो प्रतियोगिता में रंजीता ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। वर्ष 2024 में केरल में आयोजित खेलो इंडिया नेशनल जूडो टूर्नामेंट में 52 किलोग्राम वर्ग में सिल्वर मेडल प्राप्त किया। इसी वर्ष महाराष्ट्र के नासिक में आयोजित खेलो इंडिया रीजनल जूडो प्रतियोगिता में उसने गोल्ड मेडल हासिल किया। इसके साथ ही त्रिशूर (केरल) में 52 किलोग्राम वर्ग में पुनः स्वर्ण पदक प्राप्त कर अपनी श्रेष्ठता को दोहराया। पुणे में आयोजित राष्ट्रीय ओपन नेशनल जूडो चैंपियनशिप में रंजीता ने असम, तेलंगाना, महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे प्रमुख राज्यों की खिलाड़ियों को पराजित करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, पटना (बिहार) में भी उसने जूडो चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक प्राप्त कर जिले और राज्य को गौरवान्वित किया।

महानदी जागरूकता अभियान के तहत रोपे जाएंगे नारियल के 4000 पौधे

वृक्षारोपण महाभियान का आयोजन

धमतरी,। छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी महानदी के संरक्षण एवं पुनर्जीवन के उद्देश्य से एक व्यापक जनजागरण अभियान महानदी जागरूकता अभियान का आयोजन किया जा रहा है। यह अभियान न केवल पर्यावरणीय चेतना को बढ़ावा देने का कार्य करेगा, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी इस महान नदी के प्रति जनमानस में जागरूकता और संवेदनशीलता भी उत्पन्न करेगा।

इसी कड़ी में कल 18 जुलाई को प्रातः 10 बजे नगरीय विकास खंड के ग्राम बोधसेमरा, ग्राम पंचायत देवपुर में एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को फलदार पौधे भी वितरित किए जाएंगे, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में हरियाली के साथ-साथ आत्मनिर्भरता भी बढ़े। कार्यक्रम की विशेषता के रूप में, महानदी किनारे 14 किलोमीटर क्षेत्र (फरसियां से गणेशघाट तक) में लगभग 4000 नारियल के पौधे रोपित किए जाएंगे। यह वृक्षारोपण महाभियान न केवल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक मजबूत कदम है, बल्कि नदी के आसपास के पारिस्थितिकी तंत्र को सशक्त करने की दिशा में भी एक अहम प्रयास है।

योजना

जवाहर नवोदय विद्यालय, पेंटा (दोरनापाल) में छठवीं कक्षा में चयन पाकर इतिहास रच दिया

अंधेरे से उजाले की ओर : पूवर्ती गांव के अर्जुन की उड़ान

रायपुर, लोकशक्ति

नक्सलवाद से प्रभावित बस्तर अंचल का एक नाम जो आज उम्मीद और बदलाव की मिसाल बनकर उभरा है ङ्क वह है माडवी अर्जुन। सुकमा जिले के अति-दुर्गम और माओवादी हिंसा से वर्षों त्रस्त रहे पूवर्ती गांव के इस बालक ने जवाहर नवोदय विद्यालय, पेंटा (दोरनापाल) में छठवीं कक्षा में चयन पाकर इतिहास रच दिया है। यह केवल एक छात्र की जीत नहीं, बल्कि उस उम्मीद का संकेत है जो अब बस्तर के कोने-कोने में अंकुरित हो रही है। माडवी अर्जुन जिस पूवर्ती गांव का रहने वाला है , दरअसल वह नक्सलियों के कमांडर हिड़मा का पैतृक गांव है। एक दौर था, जब पूवर्ती नक्सलियों का गढ़ माना जाता था। यहाँ माओवादी जन अदालत लगाकर आतंक और ग्रामीणों भाग्य का फैसला सुनाते थे। अब वही पूवर्ती गांव, शिक्षा और विकास के नए सूरज की किरणें देख रहा है। अर्जुन की इस उपलब्धि ने यह दिखा दिया है कि परिस्थितियां कितनी भी कठिन हों, अगर अवसर और मार्गदर्शन मिले तो सफलता जरूर मिलती है। अर्जुन वर्तमान में बालक आश्रम सिलगेर में पढ़ाई कर रहा था। उसके घर में न बिजली है, न पक्की छत। उसके माता-पिता खेती और मजदूरी कर किसी तरह घर चलाते हैं। फिर भी, अर्जुन ने कठिन परिस्थितियों को पीछे छोड़ते हुए अपनी मेहनत और आश्रम शिक्षकों के समर्पण से यह उपलब्धि अर्जित की। बीते डेढ़ वर्षों में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाए जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान ने बस्तर के दूरस्थ क्षेत्रों में परिवर्तन की नींव रखी है। पूवर्ती जैसे क्षेत्र जहां पहले सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं थीं, अब वहां सड़क निर्माण, सुरक्षा बलों के कैंप, गुरुकुल विद्यालय, स्वास्थ्य सेवाएं और उचित मूल्य दुकानें शुरू हो चुकी हैं। पूवर्ती में अब बच्चों की पढ़ाई के लिए सुरक्षा बलों की देखरेख में चल रहे गुरुकुल ने एक प्रेरणादायी माहौल देना शुरू किया है। अर्जुन की सफलता इसी सतत प्रयास की पहली बड़ी उपलब्धि है। जिला कलेक्टर श्री देवेश ध्रुव ने कहा कि पूवर्ती जैसे दुर्गम और माओवाद प्रभावित गांव से नवोदय विद्यालय में चयन, न केवल अर्जुन की मेहनत का परिणाम है, बल्कि यह जिले की शिक्षा व्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन का भी संकेत है। हम हर बच्चे को आगे बढ़ाने का मौका देना चाहते हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा है कि माडवी अर्जुन की सफलता छत्तीसगढ़ की बदलती तस्वीर का प्रतीक है। यह उस नव-छत्तीसगढ़ की झलक है, जहाँ अंधेरे की जगह अब उजाले की बातें हो रही हैं। पूवर्ती जैसे गांव से राष्ट्रीय स्तर के नवोदय स्कूल तक का सफर दर्शाता है कि हमने जो बीज शिक्षा, सुरक्षा और विकास का बोया है, वह अब फल देने लगा है। अर्जुन को मेरी ओर से ढेरों बधाई और शुभकामनाएं। अब पूवर्ती क्षेत्र से केवल एक अर्जुन नहीं, हजारों अर्जुन निकलेंगे और छत्तीसगढ़ के भविष्य को संवारेंगे। राज्य सरकार हर बच्चे के सपनों को पंख देने के लिए कटिबद्ध है।

माडवी अर्जुन की यह यात्रा केवल एक छात्र की कहानी नहीं, बल्कि यह उस बदलाव की दास्तान है, जिसे बस्तर जी रहा है। नक्सलवाद की दीवारें अब दरक रही हैं और शिक्षा की रोशनी बस्तर के घर-आंगनों में फैल रही है।बदलते बस्तर की यह शुरुआत है। अब अर्जुनों की कतार लगेगी और पूवर्ती जैसे गांव विकास की नई इबारत लिखेंगे।

राष्ट्रीय स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में रायपुर देश का सबसे स्वच्छ चौथा शहर

रायपुर - लोकशक्ति। राष्ट्रीय स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में रायपुर शहर देष का सबसे स्वच्छ चैथा शहर बनने और गार्बेज फ्री सिटी में रायपुर शहर छत्तीसगढ़ का पहला 7 स्टार शहर बनने पर इस गौरव और उपलब्धि पर प्रसन्न होकर आज नगर निगम रायपुर के सफाई मित्रो और स्वच्छता दीदियों ने प्रदेश के उपमुख्यमंत्री नगरीय प्रषासन एवं विकास विभाग श्री अरूण साव का नई दिल्ली में भारत गणराज्य की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु के करकमलो से केन्द्रीय शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर और केन्द्रीय शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री तोखन साहू की उपस्थिति में छत्तीसगढ राज्य के नगर निगम रायपुर सहित 7 नगरीय निकायो को निर्धारित मानको के अनुरूप स्वच्छता में श्रेष्ट प्रदर्षन हेतु विभिन्न श्रेणियों के अवार्ड देकर शहरो को सम्मानित किया गया।

उपमुख्यमंत्री नगरीय प्रषासन एवं विकास विभाग श्री अरूण साव ने छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रषासन एवं विकास विभाग की ओर से संबंधित चयनित सम्मानित नगर निगम रायपुर सहित 7 नगरीय निकायो के पदाधिकारियों एवं अधिकारियों की उपस्थिति में स्वच्छता के श्रेष्ठता मानको के अवार्ड राष्ट्रपति श्री द्रोपदी मुर्मु के करकमलो से विज्ञान भवन नई दिल्ली में ग्रहण किये। आज सुबह उपमुख्यमंत्री नगरीय प्रषासन एवं विकास विभाग श्री अरूण साव जैसे ही माना विमानतल पर राजधानी रायपुर वापस लौटे तो नगर निगम रायपुर के सफाई मित्रो एवं स्वच्छता दीदियों ने बडी संख्या में उन्हें बुके प्रदत्त कर एवं फूल मालाओ से लादते हुए उनका प्रसन्नता पूर्वक आत्मीय स्वागत किया।

नगर निगम रायपुर के जोन कमिष्नर डॉ. आर.के. डोंगरे, डॉ. दिव्या चंद्रवंषी, श्रीमती राजेष्वरी पटेल, सर्वश्री राकेष शर्मा, हितेन्द्र यादव, विवेकानंद दुबे, संतोष पाण्डेय, रमेष जायसवाल, अरूण ध्रुव, खीरसागर नायक, कार्यपालन अभियंताओं, जोन स्वास्थ्य अधिकारियों, जोन सहायक राजस्व अधिकारियों, निगम अधिकारियों कर्मचारियों ने उनका बडी संख्या में आत्मीयता के साथ अवार्ड प्राप्त करने के उपरांत रायपुर वापस लौटने पर स्वागत किया।

निगम राजस्व निरीक्षक बल्लभ शर्मा को सेवानिवृत्ति पर जोन 4 राजस्व कर्मचारियों ने सेवाओं को किया सम्मानित

नगर निगम रायपुर द्वारा मार्गो से आवारा पशुओं को धरपकड़ कर निरंतर गौठानो में भेजा जा रहा

रायपुर - नगर पालिक निगम रायपुर की महापौर श्रीमती मीनल चैबे, स्वास्थ्य विभाग अध्यक्ष श्रीमती गायत्री सुनील चंद्राकर, आयुक्त श्री विष्वदीप के निर्देष पर नगर पालिक निगम रायपुर के सभी जोनो की टीमो द्वारा अभियान चलाकर जोन क्षेत्र के विभिन्न मुख्य मार्गो में मॉनिटरिंग करके सड़को पर आवारा पषुओ की धरपकड़ कर उन्हें गौठानो में काउकेचर वाहन से भेजे जाने की कार्यवाही निरंतर प्रगति पर है।

नगर निगम जोन 10 ने तेलीबांधा व्हीआईपी रोड पर 6 आवारा पषुओं की धरपकड़ कर उन्हें काउकेचर वाहन से गौठान भेजा । वहीं जोन 10 के तहत व्हीआईपी रोड में 6 आवारा पषुओ और देवपुरी गुरूद्वारा चैक के आस पास सडक मार्गो से 14 आवारा पषुओ को काउकेचर में धरपकड़ कर गौठान भेजा । आवारा मवेषियों की धरपकड़ का अभियान निरंतर जारी रहेगा।

युक्तियुक्तकरण अभ्यावेदन के लिए 28 तक करें आवेदन

0 संभागायुक्त महादेव कावरे की अध्यक्षता में समिति करेगी विचार

रायपुर, (आरएनएस)। शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण के पश्चात जिला स्तरीय समिति के विरुद्ध प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार संभागायुक्त महादेव कावरे की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। समिति की बैठक में निर्णय लिया गया है कि अभ्यर्थी अपना अभ्यावेदन/आवेदन आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर के नाम से संबोधित करते हुए कार्यालय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल, एकीकृत परिसर, प्रथम तल, पेंशनबाड़ा में दिनांक 16 जुलाई 2025 से 28 जुलाई 2025 तक कार्यालयीन समय में जमा कर सकते हैं। अभ्यावेदन में आवेदक जानकारी जैसे :- युक्तियुक्तकरण उपरांत आबंटित शाला का आदेश, यदि युक्तियुक्तकरण उपरांत आबंटित शाला में कार्यभार ग्रहण किया गया है, तो कार्यभार ग्रहण दिनांक, अभ्यावेदक का मोबाईल नम्बर, यदि न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की गई है तो याचिका की प्रति एवं प्रकरण पर माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया है तो निर्णय की प्रति, जिला स्तरीय युक्तियुक्तकरण समिति को प्रस्तुत अभ्यावेदन की प्रति, जिला स्तरीय युक्तियुक्तकरण समिति के निर्णय की कॉपी अनिवार्यतः संलग्न करें ।

अरूण साव का नई दिल्ली से वापस राजधानी लौटने पर विमानतल पर स्वच्छता दीदियों, सफाई मित्रों ने रायपुर निगम अधिकारियों कर्मचारियों सहित आत्मीय स्वागत किया

में छत्तीसगढ़ का पहला 7 स्टार शहर रायपुर बनने पर उपमुख्यमंत्री नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

रायपुर - राष्ट्रीय स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में रायपुर शहर देष का सबसे स्वच्छ चैथा शहर बनने और गार्बेज फ्री सिटी में रायपुर शहर छत्तीसगढ़ का पहला 7 स्टार शहर बनने पर इस गौरव और उपलब्धि पर प्रसन्न होकर आज नगर निगम रायपुर के सफाई मित्रो और स्वच्छता दीदियों ने प्रदेष के उपमुख्यमंत्री नगरीय प्रषासन एवं विकास विभाग श्री अरूण साव का नई दिल्ली में भारत गणराज्य की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु के करकमलो से केन्द्रीय शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर और केन्द्रीय शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री तोखन साहू की उपस्थिति में छत्तीसगढ राज्य के नगर निगम रायपुर सहित 7 नगरीय निकायो को निर्धारित मानको के अनुरूप स्वच्छता में श्रेष्ट प्रदर्षन हेतु विभिन्न श्रेणियों के अवार्ड देकर शहरो को सम्मानित किया गया।

उपमुख्यमंत्री नगरीय प्रषासन एवं विकास विभाग श्री अरूण साव ने छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रषासन एवं विकास विभाग की ओर से संबंधित चयनित सम्मानित नगर निगम रायपुर सहित 7 नगरीय निकायो के पदाधिकारियों एवं अधिकारियों की उपस्थिति में स्वच्छता के श्रेष्ठता मानको के अवार्ड राष्ट्रपति श्री द्रोपदी मुर्मु के करकमलो से विज्ञान भवन नई दिल्ली में ग्रहण किये।

आज सुबह उपमुख्यमंत्री नगरीय प्रषासन एवं विकास विभाग श्री अरूण साव जैसे ही माना विमानतल पर राजधानी रायपुर वापस लौटे तो नगर निगम रायपुर के सफाई मित्रो एवं स्वच्छता दीदियों ने बडी संख्या में उन्हें बुके प्रदत्त कर एवं फूल मालाओ से लादते हुए उनका प्रसन्नता पूर्वक आत्मीय स्वागत किया। नगर निगम रायपुर के जोन कमिष्नर डॉ. आर.के. डोंगरे, डॉ. दिव्या चंद्रवंषी, श्रीमती राजेष्वरी पटेल, सर्वश्री राकेष शर्मा, हितेन्द्र यादव, विवेकानंद दुबे, संतोष पाण्डेय, रमेष जायसवाल, अरूण ध्रुव, खीरसागर नायक, कार्यपालन अभियंताओं, जोन स्वास्थ्य अधिकारियों, जोन सहायक राजस्व अधिकारियों, निगम अधिकारियों कर्मचारियों ने उनका बडी संख्या में आत्मीयता के साथ अवार्ड प्राप्त करने के उपरांत रायपुर वापस लौटने पर स्वागत किया। उपमुख्यमंत्री नगरीय प्रषासन एवं विकास विभाग श्री अरूण साव ने आत्मीय स्वागत पर नगर निगम रायपुर के अधिकारियों कर्मचारियों सहित स्वच्छता दीदियों, सफाई मित्रों को धन्यवाद देते हुए रायपुर के छत्तीसगढ़ राज्य में गार्बेज फ्री सिटी में प्रथम 7 स्टार शहर बनने और राष्ट्रीय स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में देष में रैंकिंग में चैथे स्थान पर रायपुर के आने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी ।

रायपुर रेलवे स्टेशन पर विदेशी गांजा बरामद, आरोपी गिरफ्तार

रायपुर, । रायपुर रेलवे स्टेशन पर रेलवे आरपीएफ की क्राइम ब्रांच विंग ने बड़ी सफलता हासिल की है। नेपाल से लाए गए करीब 4 लाख रुपए मूल्य के 15 पैकेट गांजे के साथ एक व्यक्ति को पकड़ लिया गया है। जानकारी के मुताबिक, महानिरीक्षक एवं प्रमुसुआयुक्त बिलासपुर के मार्गदर्शन में प्रभारी निरीक्षक निशा भोईर और अन्य अधिकारियों के साथ स्टेशन पर चेकिंग के दौरान प्लेटफॉर्म नंबर 1, दुर्ग छोर के पास एक व्यक्ति को 2 बैग गांजे के साथ पकड़ा गया। आरोपी की पहचान हरिओम मिश्रा (20 वर्ष) निवासी सुगांव, थाना सुगोली, जिला मोतिहारी (बिहार) के रूप में हुई। दोनों बैग की जांच में कुल 15 पैकेट गांजे का वजन 15.370 किलोग्राम पाया गया, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 3,84,250 रुपए है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि यह गांजा पटना से रायपुर साउथ बिहार एक्सप्रेस से आया था। उसका मकसद इसे बिलासपुर पहुंचाना था, लेकिन ट्रेन में शराब के नशे की वजह से वह बिलासपुर के बजाय रायपुर आ गया। नशे की हालत में उसने यहीं आराम किया और तभी उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ आबकारी विभाग ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(ब) के तहत अपराध क्रमांक 113/2025 के तहत मामला दर्ज किया है। बरामद गांजा आबकारी विभाग के वृत्त गंज रायपुर में रखा गया है।

किक बांक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन

रायपुर, वाको इंडिया किक बांक्सिंग फेडरेशन के मार्गदर्शन में किक बांक्सिंग एसोसिएशन छग द्वारा राष्ट्रीय किक बांक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन दूसरे दिन भी इंडोर स्टेडियम बूढ़ापारामें जारी है। उक्त प्रतियोगिता में 16 जुलाई से 20 जुलाई के मध्य 33 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में 12 सौ खिलाड़ी 300 ऑफिशियल सहित 15 सौ खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि उक्त फेडरेशन खेल एवं युवा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। इंडोर स्टेडियम में आयोजित प्रतियोगिता में विजय प्राप्त करने वाले खिलाड़ी नवंबर में अबूधाबी में आयोजित अंतरराष्ट्रीय वर्ल्ड चैम्पियनशिप प्रतियोगिता में सहभागिता निभाएंगे। द्वितीय दिवस के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि पवन साय संगठन मंत्री भाजपा एवं अध्यक्षता टंकराम वर्मा केबिनेट मंत्री खेल एवं युवा मंत्रालय विशिष्ट अतिथि किरणसिंहदेव भाजपा प्रदेशाध्यक्ष, राजेश मूणत विधायक पश्चिम, राजीव अग्रवाल अध्यक्ष छग राज्य औद्योगिक विकास निगम, हिमांशु द्विवेदी संपादक आईएनएच सुभाष राव पूर्व अध्यक्ष छग गृह निर्माण एवं नमित जैन रहे।

ठेकेदार की दुपहिया वाहन चोरी करने वाला आरोपी पकड़ाया

रायपुर, राजधानी रायपुर की गंज थाना पुलिस ने दोपहिया वाहन चोरी करने वाले आरोपी शेख सोहेल को गिरफ्तार किया है तथा उसके पास से चोरी का वाहन बरामद किया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी साहेब सिंह ने थाना गंज में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह स्टेशन रोड गुरूद्वारा के पास रहता है तथा सिविल ठेकादारी का कार्य करता है जिसके लिये उसे उसके मालिक द्वारा एक्टिवा सीजी/04/के वाय/9043 दिया गया था। प्रार्थी द्वारा दिनांक 25.06.25 के रात्रि 11 बजे अरिहंत काम्पलेक्स के सामने गुरूद्वारा के पास अपनी एक्टिवा वाहन को खड़ी कर रेल्वे स्टेशन काम से गया था, वापस आया तो देखा की उसकी एक्टिवा वाहन खड़े किये हुए स्थान पर नही थी। कोई अज्ञात चोर प्रार्थी की एक्टिवा को चोरी कर फरार हो गया था। जिस पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना गंज में धारा 303(2) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। मामले में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना गंज पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण कर घटना के संबंध में प्रार्थी तथा आसपास के लोगो से विस्तृत पूछताछ कर अज्ञात अरोपी की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा घटना स्थल तथा उसके आस-पास लगे सी.सी.टी.व्ही. कैमरों के फुटेजों का अवलोकन करने के साथ-साथ अज्ञात आरोपी की पतासाजी हेतु प्रकरण में मुखबीर भी लगाये गये। इसी दौरान टीम के सदस्यों को घटना में संलिप्त आरोपी के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा आजाद चौक निवासी शेख सोहेल की पतासाजी कर पकड़ा गया। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर कड़ाई से पूछताछ करने पर उसके द्वारा दोपहिया वाहन चोरी की उक्त घटना को अंजाम देना बताया गया। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा आरोपी शेख सोहेल को गिरफ्तार ।

रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में 65 करोड़ से अधिक की चार बड़ी योजनाओं को मिली मंजूरी

लोकशक्ति

रायपुर,। राजधानी रायपुर के पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के लिए बड़ी खुशखरी आई है। छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने इस क्षेत्र के विकास के लिए कुल 65 करोड़ 45 लाख रुपये से ज्यादा की चार प्रमुख परियोजनाओं को हरी झंडी दे दी है। इन योजनाओं में महादेव घाट का सौंदर्यीकरण, एक विशाल सेंट्रल लाइब्रेरी का निर्माण, ठक्कर बापा वार्ड में पानी टंकी की स्थापना और छुइहा तालाब का विकास शामिल है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देशानुसार उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने इन परियोजनाओं की मंजूरी की जानकारी क्षेत्रीय विधायक राजेश मूणत को दी। विधायक मूणत ने मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री दोनों को इस बड़े उपहार के लिए धन्यवाद दिया और इसे डबल इंजन सरकार की जनता के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया।

परियोजनाओं का विवरण और लागत

सेंट्रल लाइब्रेरी और रीडिंग ज़ोनः

22.84 करोड़ रुपये की लागत से 1000 सीटों वाली भव्य लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा, जो रायपुर के युवाओं को अध्ययन और शोध के लिए आधुनिक सुविधाएं प्रदान करेगी।

महादेव घाट सौंदर्यीकरण (फेस-1):

19.99 करोड़ रुपये की इस योजना के तहत महादेव घाट को बेहतर स्वरूप दिया जाएगा, जिससे यह पर्यटन और स्थानीय लोगों के लिए आकर्षक स्थल बनेगा।

ठक्कर बापा वार्ड में पानी टंकी और पाइपलाइनः

19.61 करोड़ रुपये की इस परियोजना के माध्यम से वार्ड और आसपास के इलाकों में नई पानी टंकी तथा पाइपलाइन बिछाई जाएगी, जिससे साफ और पर्याप्त पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।

छुइहा तालाब का विकासः

3 करोड़ रुपये की लागत से इस तालाब का सौंदर्यीकरण एवं विकास कार्य किया जाएगा, जिससे स्थानीय लोगों के लिए बेहतर मनोरंजन और विश्राम स्थल बनेगा।

विधायक राजेश मूणत का संदेश

राजेश मूणत ने कहा कि महादेव घाट परियोजना उनके लिए विशेष महत्व रखती है, जिस पर वे लंबे समय से मेहनत कर रहे थे। उन्होंने भरोसा जताया कि इन सभी विकास कार्यों से रायपुर पश्चिम क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं में सुधार होगा और यह क्षेत्र राजधानी रायपुर के विकास में एक नया मुकाम हासिल करेगा।

उपमुख्यमंत्री का निर्देश

डिप्टी सीएम अरुण साव ने मूणत को पत्र लिखकर इन योजनाओं की निगरानी स्वयं करने और तय समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण पूरा करने का आग्रह किया है। उन्होंने मूणत के सुझावों और मार्गदर्शन पर भरोसा जताते हुए कहा कि इसी से काम और प्रभावी होगा।

जनता की भागीदारी जरूरी

विधायक मूणत ने यह भी कहा कि विकास कार्यों को सिर्फ सरकार के स्तर पर नहीं, बल्कि आम जनता के सुझावों को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि यदि वे अपने वार्ड में किसी जनहित के कार्य की आवश्यकता महसूस करें तो सीधे उनसे संपर्क करें। सभी सुझावों को गंभीरता से लिया जाएगा और संभव हो तो योजनाओं में शामिल किया जाएगा।

सरकार का विकास के प्रति संकल्प

मूनत ने स्पष्ट किया कि छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार विकास के लिए फंड की कमी नहीं आने देगी। न केवल रायपुर पश्चिम, बल्कि पूरे राज्य में विकास कार्य निरंतर जारी रहेंगे और जनता को बेहतर सेवाएं मुहैया कराई जाएंगी।

निगम उपायुक्त हालदार और राजस्व निरीक्षक बल्लभ शर्मा सेवानिवृत्त

रायपुर, राज्य नगरीय निकाय के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी नगर पालिक निगम रायपुर में उपायुक्त ए. के. हालदार को आज नगरीय निकाय सेवा से सेवानिवृत्त होने पर नगर निगम सभापति श्री सूर्यकान्त राठौड़, नगर निगम आयुक्त श्री विश्वदीप ने नगर निगम मुख्यालय महात्मा गाँधी सदन के चतुर्थ तल सामान्य सभा सभागार में बुके, श्रीफल, शाल, स्मृतिचिन्ह प्रदत्त कर रायपुर नगर निगम में जोन कमिश्नर और निगम उपायुक्त के पद पर निरन्तर 6 वर्ष तक सेवाएं देने हेतु सम्मानित किया और उन्हें सुदीर्घ, स्वस्थ, सुखी जीवन हेतु हार्दिक शुभकामनायें दीं।

सभापति श्री सूर्यकांत राठौड़ ने रायपुर नगर निगम में उपायुक्त श्री ए.के. हालदार द्वारा लगातार 6 वर्ष सेवाएं देने को सराहा व कहा कि उनकी स्पष्टवादिता सराहनीय रही है। सभापति ने उनके उज्जवल भविष्य, स्वस्थ सुखी जीवन हेतु हार्दिक शुभकामनाएं दी । सभापति ने आयुक्त से अनुरोध किया कि नगर निगम रायपुर के सेवानिवृत्त होने वाले निगम अधिकारियों व कर्मचारियों का सेवानिवृत्ति दिवस पर नगर निगम की ओर से सेवाओं का सम्मान किया जाना चाहिए और उनके स्वत्वों का भुगतान तत्काल किया जाना चाहिए।

आयुक्त विश्वदीप ने श्री ए.के. हालदार द्वारा नगर निगम की सेवा निष्ठा, लगन, कडी मेहनत से करके अपनी जिम्मेदारियों का वहन करने को सराहा। उन्होने उनके सुदीर्घ, स्वस्थ, सुखी, उज्जवल जीवन हेतु हार्दिक शुभकामनाएं दी । आयुक्त ने प्रभारी अपर आयुक्त सामान्य प्रशासन श्रीमती कृष्णा खटीक को सेवानिवृत्ति दिवस पर निगम सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से निगम अधिकारियों एवं कर्मचारियों का सम्मान कार्यक्रम मुख्यालय में रखा जाना एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों कर्मचारियों के स्वत्वों का भुगतान किया जाना सुनिश्चित करने निर्देशित किया।

सेवानिवृत्त उपायुक्त श्री ए.के. हालदार ने अपने प्रशासनिक सेवाकाल के संबंध में संस्मरण सुनाएं । उन्होने लगातार 43 वर्षों तक नगरीय निकायों की सेवा निष्ठापूर्वक ईमानदारी से की।

संपादकीय

ट्रंप की प्रतिक्रिया के मायने

फिलिस्तीन और पश्चिम एशिया के लिए कोई न्याय की बात करे यह बात नेतन्याहू और ट्रंप को हजम नहीं होती। यही कारण है कि जब ब्रिक्स देशों ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष, अस्थिरता और गाजा के खिलाफ इस्त्राइली हमलों और कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र की स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की तो ट्रंप तिलमिला उठे। जब ट्रंप अपने देश में यहूदी विरोध के बहाने अपने ही विविद्यालयों पर तमाम पाबंदियां लगा सकते हैं तो ब्रिक्स देशों की यह हरकत कैसे बर्दाश्त करते। फलस्वरूप उन्होंने इन देशों पर ही अतिरिक्त 10 प्रतिशत शुल्क लगाने की धमकी तक दे डाली। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बाद जारी संयुक्त घोषणापत्र ट्रंप के तिलमिलाने का कारण साबित हुआ। घोषणापत्र में कही गई हर बात ट्रंप और नेतन्याहू का मुंह ही नहीं चिढ़ाती, बल्कि इसकी भी झलक दिखाती है कि बदलती दुनिया क्या चाहती है। घोषणापत्र में ब्रिक्स देशों ने दोहराया कि इस्त्राइल-फिलिस्तीन संघर्ष का न्यायसंगत और स्थायी समाधान शांतिपूर्ण तरीकों से ही प्राप्त किया जा सकता है।

संस्कृति,संस्कार की होली जलाती अंग्रेजियत।

अंग्रेजों के आने के पूर्व भारतीय संस्कृति धार्मिक, आध्यात्मिक, परंपरा वादी, भाग्यवादी रही है। अंग्रेजों के भारत आने के बाद और उनके संपर्क में रहने से भारतीय जीवन का स्वरूप काफी हद तक परिवर्तित एवं बदले हुए स्वरूप में आया था । धार्मिकता आध्यात्मिकता तथा त्याग व ममता को व्यापक भौतिकवादी दृष्टिकोण से काफी नुकसान पहुंचा है। पश्चात विचारधारा के संपर्क में आने से परंपराओं के प्रति मोह धीरे-धीरे कम होने लगा एवं नई वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाली सोच के कारण भाग्य वाद के प्रति आस्था उत्पन्न होने लगी। इसके अतिरिक्त भारतीय दर्शन के आंतरिक गुणों आदर्श नैतिकता,बुद्धि आदि में भी आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं। और इन घटकों पर नवीन शिक्षा पद्धति का व्यापक प्रभाव पड़ा है। अंग्रेज भारत को ऐसा वर्ग विशेष बनाना चाहते थे, जो जन्म और रंग से तो पूर्वी हों, पर अन्य सभी दृष्टिकोण से सब अंग्रेज बने रहें। भारत का उच्च वर्ग या अमीर तबका, राजा, महाराजा,नवाब धीरे-धीरे अंग्रेजी शिक्षा के गुलाम होते चले गए,और पाश्चात्य संस्कृति की ओर झुकते गए। भारतीय संस्कृति को विस्मृत करने में यही उच्च वर्ग या अमीर लोग काफी हद तक जिम्मेदार है। यह लोग अंग्रेजियत की नकल करने लगे,तथा भारतीय समाज धर्म दर्शन में इनकी कोई रूचि अविश्वास नहीं रहने लगा था। और इनकी नकल में इनके मातहत, सिपहसालार भी उसी रंग में डूबने लगे थे। धीरे धीरे पश्चिमी सभ्यता ने भारतीय संस्कृति पर अपना व्यापक प्रभाव डालना शुरू कर दिया था। पश्चिमी संस्कृति का वृहद अध्ययन करने वाले भारतीय विद्वानों ने पश्चिम की ओर इस अंधे आकर्षण का खुलकर विरोध भी किया था। इन्हीं विद्वानों ने भारतीय जनमानस को अपनी शक्ति और धर्म में विश्वास करने की प्रेरणा देकर उनका मार्गदर्शन किया था। तत्पश्चात भारतीय शोधकर्ताओं ने पश्चिम सभ्यता तथा उसकी शिक्षा का व्यापक परीक्षण शुरू कर दिया था। और इन्हीं शोधकर्ताओं और विद्वानों की अथक मेहनत से प्राचीन परंपराओं में सर्वश्रेष्ठ का चयन कर एवं पाश्चात्य दर्शन की श्रेष्ठ धारणाओं को मिलाकर एक नए दर्शन को समाज के सामने प्रस्तुत किया था। भारतीय विद्वानों, शोधकर्ताओं एवं विचारकों ने प्राचीन भारतीय कुप्रथा जैसे छुआछूत, पर्दा प्रथा,बहु विवाह, बाल विवाह, देवदासी प्रथा एवं महिला शिक्षा, तथा निरक्षरता के विरोध में अभियान चलाकर सामाजिक चेतना का आह्वान किया था। पर पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में आकर भारतीय समाज में नैतिक विचारों में परिवर्तन की शुरुआत हुई। इस परिवर्तन के साथ भारतीय जनमानस के रहन-सहन खानपान, वेशभूषा,विवाह समारोह, आचार विचार, शिष्टाचार तथा व्यवहार में पाश्चात्य शिक्षा की झलक दिखाई देने लगी। जाति प्रथा के कठोर नियम ढीले पड़ने लगे। बाल विवाह प्रथा में बेहद कमी आने लगी। पश्चात दर्शन ने भारतीय संस्कृति में जीवंत एवं चरित्र को एक नया बदलाव दिया था। पाश्चात्य संस्कृति में धीरे-धीरे भारतीय रहन-सहन रीति-रिवाज प्रथाओं को प्रभावित किया। ड्रेसिंग सेंस, खान पान,बोलने चालने तथा अभिवादन के तरीकों में बड़े परिवर्तन हुए। वेस्टर्न पद्धति से संस्कृति शिक्षा विचारधाराओं ने भारत को दुनिया के राष्ट्रीय जीवन के संपर्क में ला खड़ा किया था। देश के अंदर विभिन्न अलग-अलग विचारधाराओं के समूहों को एक सांस्कृतिक समानता के मंच पर लाकर खड़ा किया। और इसी सांस्कृतिक समानता ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एकता और राष्ट्रीयता की नई मिसाल स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए प्रदान की थी। विहंगम दृष्टिकोण से देखा जाए तो पाश्चात्य दर्शन ने भारतीय परंपरा रीति रिवाज में महत्वपूर्ण सुधार लाने की एक नई पहल की थी। प्राचीन परंपराओं के फल स्वरुप भारतीय जनमानस को रीति-रिवाजों एवं पाखंडी पन ने जीवन में जंजीर बनकर जकड़ रखा था।

विपक्ष की लोकतंत्र पर चिंता या सत्तालोभ की राजनीति?

ललित गर्ग
लेखक, पत्रकार, स्तंभकार

-ललित गर्ग-

भारतीय लोकतंत्र आज विश्व के सबसे बड़े, जीवंत और जागरूक लोकतंत्रों में गिना जाता है। यह संविधान की मजबूत नींव, संस्थाओं की पारदर्शिता और जनता की जागरूकता से संचालित होता है। परंतु विडंबना यह है कि देश का विपक्ष, विशेषकर कांग्रेस और उनके नेता राहुल गांधी, बार-बार लोकतंत्र और संविधान पर खतरे की झूठी दुहाई देकर एक अनावश्यक और निरर्थक बहस छेड़ते रहे हैं, वे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं भाजपा को घेरने एवं दोषी ठहराने के लिये न केवल उन पर आधारहीन आरोप लगाते रहते हैं, वरन देश की संवैधानिक संस्थाओं, प्रक्रियाओं और संविधान के ही खतरे में होने का राग अलापते हुए उन्हें लांछित करने का प्रयास करते हैं। ऐसे नेता संविधान की दुहाई देते हैं, वे स्वयं संविधान और कानून की धज्जियां उड़ाते दिखते हैं। लोकतंत्र की आत्मा पर इस तरह का प्रहार विपक्ष की भूमिका पर एक बड़ा प्रश्न है। विडम्बना एवं चिन्ताजनक है कि राहुल गांधी अपनी विदेश यात्राओं में भी मोदी-भाजपा का विरोध करते-करते देश-विरोध पर उतर जाते हैं, जिससे विदेशों में भारत की छवि का भारी नुकसान होता है और विदेशियों को लगता था कि भारत में लोकतंत्र और संविधान ढह रहा है।

नेता-प्रतिपक्ष राहुल गांधी एवं उनके सहयोगी जब यह कहते हैं कि 'देश में लोकतंत्र समाप्त हो गया है', 'संविधान खतरे में है', तब यह केवल एक राजनीतिक शगूफा प्रतीत होता है, न कि कोई तर्कसम्मत आलोचना। यदि वास्तव में लोकतंत्र खतरे में होता, तो क्या वे हर मंच से खुलकर सरकार की आलोचना कर पाते? क्या संसद, मीडिया, चुनाव आयोग, और न्यायपालिका जैसी संस्थाएं उनके वक्तव्यों को स्थान देतीं? असल में तो 1975 में लोकतंत्र एवं संविधान खतरे में आये थे जब तत्कालिन प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने अपनी सरकार बचाने हेतु अनुच्छेद 352 के अंतर्गत 'आंतरिक अशांति' के आधार पर आपातकाल लगाया तथा लोकतंत्र और संविधान को दरकिनार कर हजारों नेताओं एवं बेगुनाह लोगों को कठोर कानूनों के अंतर्गत जेल भेज दिया। आजादी के बाद तब पहली और आखरी बार लोकतंत्र खतरे में आया था, तब संविधान भी खतरे में चला गया था। राहुल गांधी अपने गिरेबान में झांकने एवं कांग्रेस के अतीत को देखने की बजाय मोदी-भाजपा पर लोकतंत्र एवं संविधान को खतरे में डालने का बेबुनियाद, भ्रामक एवं आधारहीन आरोप मंढते हैं। इन त्रासद स्थितियों में यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि विपक्ष लोकतंत्र की रक्षा नहीं, बल्कि अपने खोए हुए जनाधार को पुनः प्राप्त करने के लिए लोकतंत्र को बदनाम करने का प्रयास कर रहा है। विशेषतः लोकसभा हो या विधानसभा के चुनाव-इनमें जरूरी एवं जनता से जुड़े विषयों को उठाने की बजाय लोकतंत्र एवं संविधान के खतरे में होने के राग से जनता को गुमराह करना आम बात हो गयी है।

देशभर में एवं अनेक राज्यों में बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और म्यांमार आदि के अवैध घुसपैठियें बड़ी मात्रा में घुस आये हैं। अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिये इन घुसपैठियों को इन विपक्षी दलों की शह पर ही जगह मिल रही है, ये घुसपैठियें न केवल फर्जी तरीकों से आधार, पैन, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि दस्तावेज प्राप्त कर कई निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता-सूचियों में अपना नाम अंकित करा लिया है। यह लोकतंत्र, राष्ट्रीय सुरक्षा एवं जनसंख्या संतुलन के लिए गंभीर खतरा है, चुनाव आयोग ने इस पर अपना रुख सख्त करते हुए सभी राज्यों में 'मतदाता सूचियों के गहन पुनरीक्षण' का निर्णय लिया है। बिहार में वह ऐसे लोगों की पहचान संबंधी पहल कर चुका है, पर विपक्ष को इस पर आपत्ति है और इसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती भी दी। न्यायालय ने आयोग की इस कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई।

विपक्ष लम्बे समय से चुनाव आयोग को निशाना बना रहा है, कभी निष्पक्ष मतदान पर तो कभी मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण पर सवाल उठाते रहा है। चूंकि चुनाव ही सत्ता की सीढ़ी है, इसलिए लोकसभा चुनाव में परास्त होने और अनेक राज्यों में अप्रासंगिक होने से चुनाव आयोग पर आरोप तथा लांछन लगाना विपक्ष के लिए काफी आसान हो गया है। कभी वह चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियों और निर्णयों पर अंगुली उठाता है, कभी उसे भाजपा के इशारे पर काम करने वाला बताता है, कभी ईवीएम, मतदाता सूची में अनियमितता, डाटा देने में विलंब, दलीय पक्षपात आदि का मुद्दा उठाकर चुनाव आयोग की छवि नष्ट करने का प्रयास करता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में मतदाता सूची के पुनरीक्षण को हरी झंडी देकर विपक्ष की बोलती बंद कर दी।

विपक्ष की भूमिका लोकतंत्र में रचनात्मक आलोचना और वैकल्पिक नीतियों के माध्यम से शासन को दिशा देना होती है। किंतु आज का विपक्ष न तो पाकिस्तान-चीन के खतरनाक मनसूंबों, न गरीबी, न महंगाई, न बेरोजगारी, न सांप्रदायिक सौहार्द, न सीमा पर पड़ोसी देशों की चुनौती, और न ही किसानों, युवाओं और महिलाओं की समस्याओं को लेकर कोई ठोस योजना प्रस्तुत कर पा रहा है और न ही इन बुनियादी मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठा पा रहा है। उनकी राजनीति केवल मोदी और भाजपा विरोध तक सीमित होकर रह गई है। जब राजनीति 'विकास' की बजाय 'विरोध' पर केंद्रित हो जाए, तो वह जनहित नहीं, केवल सत्ता की भूख बन जाती है।

विपक्षी दल मोदी एवं भाजपा पर लगातार आक्रामक हैं। राहुल गांधी और अन्य दलों के नेता संविधान की प्रति लहराकर यह दिखाने की कोशिश करते हैं जैसे संविधान खतरे में है और उन्हें उसे बचाना है। लेकिन भारत की जनता अब परिपक्व एवं समझदार हो गयी है, उसे अच्छा-बुरे में फर्क दिखता है। भाजपा पर 'तानाशाही', 'संविधान बदलने की साजिश', 'जनविरोधी नीतियों' जैसे आरोप लगाना विपक्ष की आदत बन चुकी है। किंतु हर बार जनता ने चुनाव में स्पष्ट बहुमत देकर इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। जनता जानती है कि ऑपरेशन सिन्दूर, डिजिटल इंडिया, गरीबमुक्त भारत, आत्मनिर्भर भारत, महिला आरक्षण, जी-20 की सफल अध्यक्षता, भ्रष्टाचार पर कार्रवाई, गरीबों के लिए मुफ्त राशन, उन्नत सड़के, चमकती रेल एवं चमकते रेल्वे स्टेशन, घर, शौचालय और जल जैसी योजनाएं सिर्फ नारों से नहीं, संकल्प और समर्पण से संभव हुई हैं।

क्या राहुल गांधी या इंडी गठबंधन के पास कोई ठोस आर्थिक नीति, सुरक्षा रणनीति, या सामाजिक समरसता का ब्लूप्रिंट है? क्या वे यह बता सकते हैं कि वे भारत को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, या केवल मोदी विरोध को ही नीति मान बैठे हैं? भारतीय जनता राजनीतिक रूप से परिपक्व हो चुकी है। वह अब भावनात्मक और भ्रामक नारों के बजाय ठोस उपलब्धियों और दूरदर्शिता को प्राथमिकता देती है। ऐसे में विपक्ष का यह दुष्प्रचार केवल उनकी साख को ही नुकसान पहुंचा रहा है। विपक्ष को चाहिए कि वह सकारात्मक राजनीति करे, वैकल्पिक नीति प्रस्तुत करे, और जनता के विश्वास को अर्जित करे, न कि लोकतंत्र के अस्तित्व को ही संदेह के घेरे में लाकर अपनी विफलताओं पर पर्दा डाले। राजनीति केवल विरोध नहीं, समाधान का माध्यम होनी चाहिए।

मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशा निर्देश

श्री अजय टम्टा
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री, भारत सरकार

पिछले कुछ सालों में लाखों ड्राइवर ऐप-आधारित टैक्सी सेवाओं से जुड़े हैं। क्योंकि इसमें उन्हें काम करने की आजादी, अनुकलता और तकनीकी सुविधा मिलती है। हालाँकि बढ़ते कमीशन, अस्पष्ट नीतियों, मनमाने निलंबन और सुरक्षा के अभाव ने इस वादे को कई लोगों के लिए निराशा में बदल दिया। भारत भर में तीन मिलियन से अधिक गिग ड्राइवरों द्वारा अनुभव की गई इन चुनौतियों ने व्यापक और लागू करने योग्य विनियमन की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित किया।

इसके जवाब में, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और श्री नितिन गडकरी के मार्गदर्शन में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) ने पहले ही मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अंतर्गत ÷मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशानिर्देश, 2020÷ जारी किये थे। इन दिशानिर्देशों ने राज्य सरकारों को एग्रीगेटर्स को लाइसेंस देने और उनकी निगरानी करने का अधिकार देते हुए एक नियामक ढाँचा प्रदान किया, जिससे वाहन-परिचालन उद्योग के विकास को बढ़ावा मिला। ड्राइवरों और यात्रियों दोनों के लिए सुरक्षा, निष्पक्षता और जवाबदेही से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने अब मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशानिर्देश, 2025 पेश किया है। ÷यह भारत के डिजिटल मोबिलिटी इकोसिस्टम में संरचना, सुरक्षा और समावेशिता लाने के लिए एक प्रमुख नीतिगत अपडेट है÷।

मोटर वाहन अधिनियम 1988 के कानूनी आधार पर निर्मित इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य ओला, उबर, रैपिडो जैसे ऐप-आधारित कैब एग्रीगेटर्स के संचालन को विनियमित करना है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि दिशानिर्देश संवैधानिक कार्यादेशों और न्यायिक निर्देशों के अनुरूप ड्राइवरों और यात्रियों दोनों को संतुलित लाभ प्रदान करने का प्रयास करते हैं।

2025 के दिशानिर्देशों का सबसे उल्लेखनीय पहलू है- ड्राइवरों के हितों की सुरक्षा। अब तक एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म से जुड़े ड्राइवर, अक्सर खुद को कम कमाई, मनमाने ढंग से कार्य से हटाना (ऑफ-बोर्डिंग), बीमा का न होना और अपर्याप्त कानूनी उपायों के साथ अनिश्चित परिस्थितियों के बीच काम करते थे। नए नियम दिशानिर्देश इन प्रणालीगत कमियों को दूर करने का प्रयास करते हैं।

दिशानिर्देशों में एग्रीगेटर्स को राज्यों द्वारा अधिसूचित मूल किराए के आधार पर प्रति घंटे या न्यूनतम गारंटीकृत आय सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। इसमें यह भी अनिवार्य किया गया है कि एग्रीगेटर और ड्राइवर के बीच किराया निपटान, आपसी सहमति से दैनिक, साप्ताहिक या पाक्षिक आधार पर किया जाना चाहिए। इस कदम से हजारों ड्राइवरों को खासकर आय-प्राप्ति वाले समय में, आय में होने वाले उतार-चढ़ाव से निजात मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा, सरकार ने अब प्रत्येक एग्रीगेटर को कम से कम 5 लाख रूपये का स्वास्थ्य बीमा और 10 लाख रूपये का सावधि बीमा प्रदान करना अनिवार्य कर दिया है। उम्मीद है कि ये सुरक्षा उपाय गिग श्रमिकों को औपचारिक श्रम संरचनाओं के दायरे में लायेंगे।

इसके अलावा, नए दिशानिर्देश कमीशन में पारदर्शिता लाते हैं तथा एग्रीगेटर के हिस्से को अधिकांश मामलों में प्रत्येक किराए के 20त्न तक सीमित करते हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है, कि ड्राइवर अपनी आय का एक उचित हिस्सा रख सकेंगे। एग्रीगेटर्स को भुगतान कटौती, किराया विभाजन और जुर्माने के बारे में स्पष्ट और विस्तृत जानकारी भी प्रदान करनी होगी।

दिशानिर्देशों में कहा गया है कि प्रत्येक एग्रीगेटर एक औपचारिक शिकायत निवारण प्रणाली की स्थापना करेगा, जहाँ यात्रा रद्दीकरण, भुगतान विवाद या निलंबन जैसे मुद्दों का समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से समाधान हो सके। ड्राइवरों को समय- समय पर प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, जिसमें ऐप उपयोग, आपातकालीन प्रतिक्रिया, सड़क सुरक्षा, यातायात नियम, लैंगिक संवेदनशीलता, दिव्यांगजन जागरूकता, ग्राहक से बातचीत, डिजिटल साक्षरता आदि विषयों पर आधारित 40 घंटे का प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल होगा, ताकि वे भविष्य के यातायात से जुड़ी चुनौतियों के लिए बेहतर ढंग से तैयार हो सकें।

यात्रियों के लिए भी ये दिशानिर्देश समान रूप से परिवर्तनकारी हैं। यात्रा सुरक्षा, डेटा गोपनीयता और किराए में हेरफेर से जुड़ी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए नए दिशानिर्देश सुरक्षा उपाय लेकर आए हैं, जिनकी बहुत आवश्यकता थी।

एग्रीगेटर प्लेटफ़ॉर्म पर सभी ड्राइवरों को अनिवार्य पुलिस सत्यापन, स्वास्थ्य जांच और व्यवहार प्रशिक्षण से गुजरना होगा। इसके अलावा, प्रत्येक वाहन में इन ऐप आपातकालीन बटन, जीपीएस-आधारित निगरानी और यात्राओं को साझा करने की सुविधाएँ होनी चाहिए, जो सभी यात्रियों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को बढ़ाती हैं। राज्य की निगरानी में एग्रीगेटर्स द्वारा एक 24×7 नियंत्रण कक्ष और हेल्पलाइन प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए।

यात्रियों के लिए एक और बड़ा लाभ किरायों और विशेष परिस्थितियों में किराये में वृद्धि (सर्ज प्राइसिंग) का नियमन है। दिशानिर्देशों में स्पष्ट सीमाएँ निर्धारित की गई हैंः राज्य की नीति के आधार पर किराए में वृद्धि की सीमा आधार किराए के 1.5 से 2 गुना तक सीमित की गयी है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उच्च माँग के समय यात्रियों का शोषण न हो। इसके अलावा, प्लेटफ़ॉर्म को किराए का विवरण पारदर्शी रूप से प्रदर्शित करना आवश्यक है, जिसमें आधार किराया, गतिशील शुल्क, एग्रीगेटर का हिस्सा और सरकारी कर शामिल हैं।

महत्वपूर्ण रूप से, दिशानिर्देश उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता का भी ध्यान रखते हैं। एग्रीगेटर्स को भारत-स्थित सर्वरों पर उपयोगकर्ता डेटा का संग्रह करने और डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम सहित डेटा सुरक्षा रूपरेखा का पालन करने का निर्देश दिया गया है, ताकि डेटा का दुरुपयोग या लीक न होना सुनिश्चित हो सके और भारत की संप्रभु डेटा नीतियों के अनुसार इसे सुरक्षित रखा जा सके।

प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारतञ्च2047 के विजन, जो समावेशी और सतत विकास पर जोर देता है तथा दिव्यांगजनों के सम्मान और स्वाभिमान को बनाए रखने के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता के अनुरूप, दिशानिर्देश में इस बात को अनिवार्य किया गया है कि एग्रीगेटर बेड़े का एक हिस्सा दिव्यांगजनों के अनुकूल बनाएं और कार्यबल में ड्राइवरों के रूप में दिव्यांगजनों का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करें। ऐसे वाहनों की संख्या राज्यों द्वारा स्थानीय जरूरतों और आवश्यकताओं के आधार पर निर्धारित की जाएगी।

स्थायित्व के लिए एक बड़े प्रयास के तहत, एग्रीगेटर्स को अपने बेड़े में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, वैकल्पिक ईंधन या शून्य उत्सर्जन वाले वाहनों को शामिल करने की आवश्यकता है। संबंधित वायु नियामक निकाय वाहन-परिचालन प्लेटफार्मों के लिए राज्यवार ईवी लक्ष्य निर्धारित करेंगे, तथा यह भारत के जलवायु और स्वच्छ वायु लक्ष्यों के अनुरूप है। दिल्ली की 'देवी' (डीईवीआई) बसें जैसी सार्वजनिक परिवहन प्रणालियाँ ईवी एकीकरण के उदाहरण हैं, जो पहले से ही मौजूद हैं।

ये दिशानिर्देश राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों, विशेष रूप से अनुच्छेद 39 के अनुरूप हैं, जो राज्य को निर्देश देता है कि गिग श्रमिकों सहित नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, संविधान के अनुच्छेद 21, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, की न्यायालयों द्वारा की गयी व्याख्या में सुरक्षित कार्य वातावरण के अधिकार और सम्मान के साथ आवागमन के अधिकार को शामिल किया गया है।

कई न्यायिक निर्णयों ने यात्रा वाहन परिचालन क्षेत्र में उचित नियमन की आवश्यकता पर बल दिया है। पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ (1982) और ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम (1985) में, सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 2 के एक अभिन्न अंग के रूप में आजीविका के अधिकार पर जोर दिया। उबर इंडिया सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ (2020) के मामले में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने एग्रीगेटर के मूल्य निर्धारण और लाइसेंस प्रक्रिया को विनियमित करने के राज्य सरकारों के अधिकार को बरकरार रखा, जहाँ यह कहा गया कि उपभोक्ता हितों को पूरी तरह से बाजार-संचालित मूल्य निर्धारण मॉडल के ऊपर रखा जाना चाहिए।

ये फैसले 2025 के दिशानिर्देशों के तहत गिग श्रमिकों को दी गई कई सुरक्षाओं के कानूनी आधार हैं। दिशानिर्देश मोटर वाहन एग्रीगेटर्स के लाभ और यात्रियों के हितों के बीच संतुलन बनाने का एक प्रयास है, साथ ही यह अक्सर उपेक्षित गिग श्रमिकों के अधिकारों को प्राथमिकता देता है।

माननीय प्रधानमंत्री के न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन के दृष्टिकोण के अनुरूप, नए दिशानिर्देश एक सरल नियामक प्रणाली प्रदान करते हैं। अब एग्रीगेटर 60 दिनों के भीतर सभी राज्यों में लागू सभी प्रकार के मोटर वाहनों के लिए एकल लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। इससे यात्री वाहन परिचालन कंपनियों के लिए ड्राइविंग टेस्ट सुविधा की व्यवस्था करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। इसके बजाय, अब उन्हें मंत्रालय की वाहन परिचालन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (आईडीटीआर), क्षेत्रीय वाहन परिचालन प्रशिक्षण केंद्र (आरडीटीसी) और वाहन परिचालन प्रशिक्षण केंद्र (डीटीसी) योजना का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित इन केंद्रों का उद्देश्य दूरदराज के क्षेत्रों में भी वैज्ञानिक प्रशिक्षण को सुलभ बनाना है, जिसमें जनसंख्या और भौगोलिक स्थिति के आधार पर आईडीटीआर के लिए 17.25 करोड़ रुपये, आरडीटीसी के लिए 5.5 करोड़ रुपये और डीटीसी के लिए 2.5 करोड़ रुपये तक का अनुदान दिया जाता है।

ये संस्थान न केवल व्यक्तियों को उच्च-गुणवत्ता वाले वाहन परिचालन कौशल प्रदान कर रहे हैं, बल्कि देश भर में पेशेवर रूप से प्रशिक्षित ड्राइवरों का एक समूह बनाने में भी योगदान दे रहे हैं। इस पहल से सड़क सुरक्षा बढ़ाने और भारतीय सड़कों पर यातायात दुर्घटनाओं को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान मिलने की उम्मीद है। सरकार ने वर्ष 2030 तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को 50त्न तक कम करने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है, यह स्वीकार करते हुए कि वर्तमान में सड़क दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में अनुमानित 3त्न का आर्थिक नुकसान होता है।

इन दिशानिर्देशों का जारी होना भारत के मज़बूत संघीय ढाँचे और संवैधानिक प्रावधानों को प्रतिबिंबित करता है। भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार परिवहन समवर्ती सूची का विषय है, जो राज्यों को एग्रीगेटर्स के लाइसेंस और संचालन के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है। अधिनियम की धारा 93 विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह केंद्र सरकार को इस उद्देश्य के लिए ऐसे दिशानिर्देश या लाइसेंस प्रक्रिया जारी करने में सक्षम बनाती है।

यद्यपि केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए, मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशानिर्देश 2025 का राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा स्थानीय अनुकूलन सुनिश्चित करते हुए पालन किया जा सकता है। लेकिन, राज्यों को अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित अधिकार दिए गए हैं। एग्रीगेटर्स को लाइसेंस जारी करना, किराया संरचना और उच्च मांग की अवधि में किराया वृद्धि (सर्ज प्राइसिंग) की निगरानी करना, चालक प्रशिक्षण और सत्यापन लागू करना, अनुपालन का उल्लंघन करने वाले प्लेटफार्मों को दंडित करना, साझा गतिशीलता मॉडल के तहत यात्रियों के लिए गैर-परिवहन मोटरसाइकिलों के उपयोग को अधिकृत करना, एग्रीगेटर बेड़े के लिए इलेक्ट्रिक वाहन लक्ष्य निर्धारित करना और उन्हें लागू करना।

ज़िम्मेदारियों का यह विभाजन भारत के सहकारी संघवाद के मॉडल को प्रतिबिंबित करता है, जहाँ नीति निर्माण केंद्रीकृत है, लेकिन कार्यान्वयन संदर्भ-संवेदनशील और राज्य-विशिष्ट है।

मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशानिर्देश, 2025 भारत के डिजिटल मोबिलिटी इकोसिस्टम में सुधार की दिशा में एक प्रगतिशील और समय-अनुकूल कदम है। इस पहल की सफलता प्रभावी कार्यान्वयन, जन जागरूकता और प्लेटफ़ॉर्म अनुपालन पर निर्भर करेगी। यदि राज्य इसका पालन करते हैं, तो इसमें यात्री वाहन परिचालन सेवाओं को शहरी परिवहन के एक सुरक्षित, अधिक जवाबदेह और अधिक समावेशी साधन में बदलने की क्षमता है, जो पूरे देश में ड्राइवरों और यात्रियों दोनों के लिए फायदेमंद साबित होगा।

ऐसे देश में जहाँ अनौपचारिक श्रमिकों का नीति-निर्माण में अक्सर प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता है, ये दिशानिर्देश एक महत्वपूर्ण बदलाव के प्रतीक हैं। ये दिशानिर्देश ऐप-आधारित ड्राइवर को न केवल एक सेवा प्रदाता के रूप में बल्कि अधिकारों, सम्मान और आकांक्षाओं वाले एक श्रमिक के रूप में देखते हैं। ये दिशानिर्देश यात्री को केवल एक उपभोक्ता के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे नागरिक के रूप में मान्यता देते हैं जो सुरक्षित, सस्ती और पारदर्शी सेवाओं का हकदार है। मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशानिर्देश, 2025 भारत में डिजिटल मोबिलिटी क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। एग्रीगेटर्स के लिए स्पष्ट मानक और ज़िम्मेदारियाँ निर्धारित करके, ये दिशानिर्देश ड्राइवरों के लिए उचित आय और सामाजिक सुरक्षा, यात्रियों के लिए बेहतर सुरक्षा और सुविधा तथा पर्यावरण की दृष्टि से सतत प्रथाओं पर ज़ोर देते हैं। यह संतुलित और समावेशी फ्रेमवर्क न केवल भारत की बढ़ती गिग अर्थव्यवस्था की नींव को मज़बूत करता है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण के भी अनुरूप है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने मिशन कर्मयोगी को सिविल सेवा सुधार का एक वैश्विक मॉडल कहा

मोदी सरकार ने सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के बीच की असंगत बाधाओं को समाप्त किया, जिससे सभी क्षेत्रों से सर्वोत्तम प्रथाओं का उपयोग संभव हुआः डॉ. जितेंद्र सिंह

''मोदी सरकार ने सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के बीच की असंगत बाधाओं को समाप्त किया, जिससे सभी क्षेत्रों से सर्वोत्तम प्रथाओं का उपयोग संभव हुआ।÷ यह बात केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी; पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा प्रधानमंत्री कार्यालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने यहां सिविल सेवा अधिकारी संस्थान (सीएसओआई) में 'सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानक 2.0' (एनएससीएसटीआई 2.0) के शुभारंभ के दौरान कही। क्षमता निर्माण आयोग (सीबीसी) द्वारा विकसित यह संशोधित संरचना भविष्य के लिए तैयार सिविल सेवा के निर्माण के भारत के अभियान में एक लंबी छलांग है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने शुभारंभ के दौरान कहा, ÷यह मील का पत्थर इसलिए संभव हुआ है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हमेशा नई सोच के लिए हमें प्रोत्साहित किया है और अतीत के वर्जनाओं को तोड़ने के लिए सशक्त बनाया है। एनएससीएसटीआई 2.0 केवल एक अनुपालन उपकरण नहीं है बल्कि यह संस्थागत उत्कृष्टता के लिए एक परिवर्तनकारी कदम है।÷

मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह संरचना किस प्रकार सहकारी एवं प्रतिस्पर्धी संघवाद का समर्थन करता है और संस्थानों को स्व-मूल्यांकन और उन्नयन करने में सक्षम बनाता है। उन्होंने कहा, ÷जिस प्रकार आकांक्षी जिला कार्यक्रम ने पिछड़े जिलों को उम्मीदों से आगे बढ़ने में सक्षम बनाया उसी प्रकार एनएससीएसटीआई 2.0, सीएसटीआई को आत्मनिरीक्षण, नवाचार एवं उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है।÷

उन्नत एनएससीएसटीआई 2.0 संरचना सिविल सेवा प्रशिक्षण के लिए ज्यादा परिष्कृत, समावेशी तथा भविष्य के लिए तैयार दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। इसे सरल एवं सुव्यवस्थित बनाया गया है, मूल्यांकन मानदंडों की संख्या 59 से घटाकर 43 की गई है, जिससे ज्यादा स्पष्टता प्राप्त हुई है और परिणाम-आधारित मूल्यांकन पर ज्यादा ध्यान केंद्रीत किया गया है। यह संरचना क्षेत्र-आधारित है जिसे 160 से ज़्यादा सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों (सीएसटीआई), मूल्यांकनकर्ताओं और क्षेत्र विशेषज्ञों के साथ व्यापक विचार-विमर्श कर तैयार किया गया है, जो इसे वास्तविक दुनिया की प्रशिक्षण चुनौतियों एवं आवश्यकताओं के साथ मेल खाता है। इसका समावेशी डिज़ाइन इसे सरकार के सभी स्तरों केंद्र, राज्य और शहरी स्थानीय निकायों के प्रशिक्षण संस्थानों के अनुकूल बनाता है।

बदलते शिक्षण परिदृश्य के मद्देनजर यह संरचना डिजिटल रूप से संरेखित है तथा इसमें हाइब्रिड शिक्षण मॉडल और एआई-संचालित प्रशिक्षण तंत्र भी शामिल किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि यह दूरदर्शी है तथा इसमें भारतीय ज्ञान प्रणाली (आईकेएस), कर्मयोगी योग्यता मॉडल (केसीएम) और अमृत ज्ञान कोष (एजीके) जैसे प्रगतिशील तत्वों को एकीकृत किया गया है, जिससे यह भविष्य के लिए तैयार, सक्षम एवं नागरिक-केंद्रित सिविल सेवा के निर्माण के भारत के दृष्टिकोण के साथ मेल खाता है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने आगे कहा, ÷मोदी सरकार ने सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के बीच की अनुचित बाधाओं को समाप्त किया है, जिससे सभी क्षेत्रों की सर्वोत्तम प्रथाओं का उपयोग संभव हुआ है। यह संरचना इसी दृष्टिकोण का परिणाम है।÷

विदेश मंत्री एस. जयशंकर नई दिल्ली में वायु सेना स्कूल के 70वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान।

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में संगम के पास मानसून के मौसम में उफनती गंगा नदी के कारण आस-पास के इलाकों में बाढ़ आने से बड़े हनुमान मंदिर आंशिक रूप से जलमग्न हो गया।

वित्त वर्ष 2025-26 में सरकार ने भारतीय डाक को दिया 20-30 प्रतिशत की ग्रोथ का टारगेट

नई दिल्ली ।

सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 में भारतीय डाक के लिए विभिन्न क्षेत्रों में 20 से 30 प्रतिशत की महत्वाकांक्षी वृद्धि का लक्ष्य रखा है। यह बयान केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की ओर दिया गया। इसका लक्ष्य भारतीय डाक को उसकी सामाजिक जिम्मेदारी से समझौता किए बिना मुनाफा में लाना है।

सिंधिया ने प्रदर्शन मानकों, नवाचार और जवाबदेही को प्राथमिकता देने वाली कॉर्पोरेट-शैली की संरचना को अपनाने के लिए भारतीय डाक की प्रशंसा की। केंद्रीय मंत्री ने कहा, भारतीय डाक केवल एक सेवा नहीं है, बल्कि हमारे देश के सुदूर कोनों को जोड़ने वाली एक जीवनरेखा है। देश के हर कोने से ऊर्जा, प्रतिबद्धता और विचारों को देखकर गर्व होता है। नई दिल्ली में इंडिया पोस्ट के 'वार्षिक व्यावसायिक सम्मेलन 2025-26' में बोलते हुए, केंद्रीय मंत्री ने एक पेशेवर, सेवा केंद्रित संस्कृति विकसित करने के महत्व पर जोर दिया, जिससे भारतीय डाक आम लोगों को सेवाएं देते हुए लॉजिस्टिक्स और वित्तीय सेवाओं में सशक्त प्रतिस्पर्धा कर सके।

बी.स.ए. के कलाकारों को ग्रीनीज बुक ऑफ़ वर्ल्ड मिलना गौरव की बात

केसिंगा। आज स्थानीय वृंदावन संस्कृत अनुष्ठान के सभा गृह में अनुष्ठान के कलाकारों का सम्मानित किया गया । विगत जनवरी 26 को दिल्ली के लाल किल्ले के मैदान में इस अनुष्ठान के कलाकारों का किया गया कला प्रदर्शन को देखकर के इन्हें ग्रीनीज बुक ऑफ वर्ल्ड से नवाजा गया था ।

आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिल्ला के जिल्ला पाल सचिन पवार महोदय एवं सम्मानित अतिथि के तौर पर केसिंगा के वरिष्ठ समाज सेवी एवं सिटीजन फॉर्म के अध्यक्ष डॉक्टर हेमसागर साह स्थानीय वीडियो, तहसीलदार जिल्ला के कई जाने माने हस्तियां उपस्थित थे। अनुष्ठान के सभापति श्री सुशांन्त महापात्र महासचिव अक्षय कुमार दास इनके अलावा केसिंगा शहर के भारी संख्या में भाई-बहन उपस्थित थे ।

इस कार्यक्रम को सफ्ल बनाने के लिए अनुष्ठान के सदस्यों का भारी योगदान रहा है। सभा का संचालन सुश्री रुबिका चौधरी ने किया एवं आखरी में धन्यवाद ज्ञापन अक्षय दास ने दिया।

वित्त वर्ष 2025-26 में सरकार ने भारतीय डाक को दिया 20-30 प्रतिशत की ग्रोथ का टारगेट : केंद्रीय मंत्री

नई दिल्ली ।

सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 में भारतीय डाक के लिए विभिन्न क्षेत्रों में 20 से 30 प्रतिशत की महत्वाकांक्षी वृद्धि का लक्ष्य रखा है। यह बयान केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की ओर दिया गया। इसका लक्ष्य भारतीय डाक को उसकी सामाजिक जिम्मेदारी से समझौता किए बिना मुनाफा में लाना है। सिंधिया ने प्रदर्शन मानकों, नवाचार और जवाबदेही को प्राथमिकता देने वाली कॉर्पोरेट-शैली की संरचना को अपनाने के लिए भारतीय डाक की प्रशंसा की। केंद्रीय मंत्री ने कहा, भारतीय डाक केवल एक सेवा नहीं है, बल्कि हमारे देश के सुदूर कोनों को जोड़ने वाली एक जीवनरेखा है। देश के हर कोने से ऊर्जा, प्रतिबद्धता और विचारों को देखकर गर्व होता है। नई दिल्ली में इंडिया पोस्ट के 'वार्षिक व्यावसायिक सम्मेलन 2025-26' में बोलते हुए, केंद्रीय मंत्री ने एक पेशेवर, सेवा केंद्रित संस्कृति विकसित करने के महत्व पर जोर दिया, जिससे भारतीय डाक आम लोगों को सेवाएं देते हुए लॉजिस्टिक्स और वित्तीय सेवाओं में सशक्त प्रतिस्पर्धा कर सके।

केंद्र सरकार की नई पहलः

रोजगार आधारित प्रोत्साहन योजना नए कर्मचारियों के साथ नियोक्ताओं के लिए भी प्रोत्साहन राशि

पीआईबी।

केंद्र सरकार द्वारा विनिर्माण क्षेत्र में नए रोजगार सृजन, कामगारों के लिए समाजिक सुरक्षा क्षेत्र का विस्तार करने और उन्हें आर्थिक स्थिरता प्रदान करने के उद्देश्य से रोजगार आधारित प्रत्साहन योजना (ईएलआई) की घोषणा की गई है।

दिनांक 01 अगस्त 2025 से प्रारंभ की जा रही इस योजना के अंतर्गत पहली बार नौकरी लगने और कर्मचारी का यूएएन (UAN) जनरेट होने पर कर्मचारी को प्रोत्साहन के तौर पर छै-छै महीनों के अंतराल में दो किश्तों में अधिकतम 15000/ रू. की राशि प्रदान की जाएगी और दूसरी ओर भविष्य निधि अधिनियम के अंतर्गत पंजिकृत संस्थानों के नियोक्तओं को नए रोजगार सृजन पर एवं 06 माह के समापन पर प्रति कर्मचारी अधिकतम 3000/ रु. की प्रोत्साहन राशि सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी ।

इस योजना के क्रियान्वयन से नए रोजगारों के सृजन के साथ ही कामगारों को आर्थिक स्थिरता प्राप्त होगी । इस योजना का लाभ दिनांक 01 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच सृजित रोजगार पर लागू होगा जिसके अंतगत एक लाख रु. तक वेतन पाने वाले कर्मचारी ही इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे । प्रोत्साहन राशि की पहली किश्त 06 माह की सेवा और दूसरी किश्त 12 महीने की सेवा के साथ ही कर्मचारी द्वारा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा करने के बाद ही प्रदान की जाएगी । विनिर्माण/उत्पादन क्षेत्र के संस्थानों के लिए यह योजना दिनांक 01 अगस्त से 31 जुलाई 2029 तक एवं अन्य संस्थानों के लिए दिनांक 01 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक प्रभावी होगी ।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय,रायपुर के प्रभारी, क्षेत्रीय आयुक्त श्री जयवदन इंगले ने केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी तथा बहुआयामी योजना के विषय में जानकारी देते हुए बताया कि ईएलआई योजना का लक्ष्य 99,446 करोड रू. के व्यय के साथ आगामी दो वर्षो की अवधि में 3.5 करोड से अधिक रोजगार के सृजन को प्रोत्साहित करना है । उन्होंने यह भी बताया कि छत्तीसगढ राज्य के श्रमिक संगठनों, संस्थानों के नियोक्ताओं एवं कर्मचारियों को ईएलआई योजना के लाभों के बारे में जागरुक करने के लिए एक विशेष जागरुकता अभियान चलाया जा रहा है ।

गूगल ' दक्षिण कोरिया में स्टैंडअलोन यूट्यूब सब्सक्रिप्शन शुरू करने की बना रहा योजना

एजेंसी।

गूगल दक्षिण कोरिया में यूट्यूब वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए एक स्टैंडअलोन प्रीमियम सब्सक्रिप्शन प्लान शुरू करने की योजना बना रहा है, जिसमें म्यूजिक स्ट्रीमिंग का विकल्प नहीं होगा। देश के एंटीट्रस्ट रेगुलेटर ने मंगलवार को कहा कि यह निर्णय दक्षिण कोरिया की कथित प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रथा को दूर करने के लिए एक स्वैच्छिक सुधारात्मक उपाय के रूप में लिया गया है।

योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, फेयर ट्रेड कमीशन (एफटीसी) के अनुसार, यूट्यूब प्रीमियम लाइट नाम से इस स्टैंडअलोन प्रोडक्ट की कीमत मौजूदा यूट्यूब प्रीमियम प्लान की कीमत से लगभग आधी होगी, जिसमें वीडियो और म्यूजिक स्ट्रीमिंग दोनों फीचर्स होंगे।

एफटीसी ने कहा कि एंड्रॉइड यूजर्स यूट्यूब प्रीमियम लाइट की मेंबरशिप 8,500 वॉन (6.15 अमेरिकी डॉलर) प्रति माह पर ले सकते हैं, जबकि आईओएस यूजर्स के लिए मासिक कीमत 10,900 वॉन निर्धारित की गई है।

नए सब्सक्रिप्शन प्लान को गूगल की सुधारात्मक कार्य योजना के रूप में प्रस्तावित किया गया था ताकि यूट्यूब म्यूजिक को वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की विज्ञापन-मुक्त प्रीमियम सब्सक्रिप्शन सर्विस के साथ बंडल करने की उसकी प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथा को संबोधित किया जा सके।

2020 में गूगल द्वारा इस तरह के प्रोडक्ट के लॉन्च के बाद एफटीसी ने 2023 में अमेरिकी तकनीकी दिग्गज द्वारा कोरिया के निष्पक्ष व्यापार नियमों के कथित उल्लंघन की जांच शुरू की।

एफटीसी ने गूगल पर ग्राहकों को दोनों सर्विस की सदस्यता लेने के लिए प्रभावी रूप से मजबूर करने, उन लोगों के लिए विकल्प सीमित करने का आरोप लगाया है जो शायद केवल विज्ञापन-मुक्त वीडियो स्ट्रीमिंग तक पहुंच चाहते थे, जिससे उपभोक्ता विकल्प सीमित हो गए और उसके बाजार प्रभुत्व का दुरुपयोग हुआ।

लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के बजाय गूगल ने एफटीसी की 'सहमति निर्णय' नामक प्रक्रिया के तहत स्टैंडअलोन वीडियो स्ट्रीमिंग सब्सक्रिप्शन प्लान शुरू करने की एक सुधारात्मक कार्य योजना प्रस्तुत की है। यह व्यवस्था एफटीसी को अपनी जांच सस्पेंड करने की अनुमति देती है अगर कंपनी स्वेच्छा से ऐसे उपाय प्रस्तावित करती है जो कथित उपभोक्ता नुकसान को दूर करते हैं।

एफटीसी ने कहा कि वह गूगल के प्रस्ताव को स्वीकार करने या न करने पर अंतिम निर्णय लेने से पहले 14 अगस्त तक 30 दिनों की अवधि में संबंधित मंत्रालयों और हितधारकों से राय एकत्र करने की योजना बना रहा है।

ट्रूहोम फाइनेंस लिमिटेड
(पूर्व नाम श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड)

Truhome FINANCE

पंजीकृत कार्यालय: श्रीनिवास टॉवर, पहली मंजिल, दरवाजा नंबर 5, पुराना नंबर 11, दूसरी लेन, सेनाटोफा रोड, अलवरपेट, तेनाम्पेट, चेन्नई-600018 **मुख्य कार्यालय**: लेवल 3, वॉकहार्ट टॉवर्स, ईस्ट विंग सी-2 ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा डु कासी, मुंबई-400051 **वेबसाइट**: www.truhomefinance.in

कब्ज़ा नोटिस

जबकि, नीचे हस्ताक्षरकर्ता, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के अंतर्गत ट्रूहोम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड) का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 13(12) के साथ पठित (नियम 3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उधारकर्ताओं को मांग नोटिस जारी किया, जिसका विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है, ताकि नोटिस प्राप्त होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर नोटिस में उल्लिखित राशि चुकाई जा सके।

उधारकर्ता द्वारा राशि वापस करने में असफल रहने के कारण, उधारकर्ता और आम जनता को सूचित किया जाता है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित, वर्ष 2025 की जुलाई माह की 14 तारीख को नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ता और आम जनता को इस संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन ट्रूहोम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड) के प्रभार के अधीन होगा, जो नीचे उल्लिखित राशि और उस पर ब्याज के रूप में होगा।

[उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जो सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में है।]

उधारकर्ता का नाम और पता

1. श्री राम कुमार रजक, पुत्र - श्री बजरंग प्रसाद रजक (उधारकर्ता)
2. श्री बजरंग प्रसाद रजक, पुत्र - श्री मूलचंद रजक (सह-उधारकर्ता)
पता मकान नंबर 6/193, राम मंदिर के पीछे, मातृछाया, तिलकनगर, चंटापारा, बिलासपुर, छ.ग. - 495001
3. त्रिकोणा फाइनेंशियल सर्विसेज (मालिक - श्री राम कुमार रजक पुत्र श्री बजरंग प्रसाद रजक)
पता - कुदुदंड, विद्या सदन, सेफ़र स्कूल के सामने, मुंगेली नाका रोड, बिलासपुर, छ.ग. - 495001

डिमांड नोटिस के अनुसार देय राशि

कुल रु. 33,86,935/- 10/03/2025 तक
ऋण खाता संख्या SBTHBILA0000195 और STUHBILA0000201
मांग सूचना की तिथि - 11-03-2025
प्रतीकात्मक कब्जे की तिथि - 14.07.2025
एनपीए की तिथि - 05.03.2025

बंधक संपत्ति का विवरण

अचल संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा, नजूल भूमिस्वामी भूमि और मकान, नजूल मोहल्ला चांटापारा में स्थित है, जिसका नजूल शीट क्रमांक 08, प्लॉट क्रमांक 5/11, नगर निगम बिलासपुर सीमा, तहसील और जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में है। क्षेत्रफल 2571 वर्ग फीट है।

स्थान : बिलासपुर
तिथि : 14-07-2025

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी- ट्रूहोम फाइनेंस लिमिटेड
(पहले श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)

बिजली दर वृद्धि के खिलाफ कांग्रेसियों का फुटा आक्रोश

सरकार विरोधी नारों के साथ सौंपा ज्ञापन

जांजगीर चांपा / बिजली दर वृद्धि के खिलाफ कांग्रेसियों ने जमकर आक्रोश व सरकार विरोधी नारों के साथ विद्युत मंडल कार्यालय नवागढ़ का घेराव कर ज्ञापन सौंपा है । यह घेराव कार्यक्रम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर ब्लाक कांग्रेस कमेटी द्वारा ब्लॉक मुख्यालय नवागढ़ राछाभाठा में आयोजित किया गया था। बिजली बिल भाजपा सरकार द्वारा बढ़ोतरी दर को वापस लेने की मांग को लेकर कनिष्ठ यंत्री बिजली आफिस कार्यालय घेराव अंबेडकर चौक राछा भाठा से निकलकर कांग्रेस जन द्वारा नारे बाजी करते हुए मुख्यमंत्री के नाम कनिष्ठ यंत्री को सोपा गया ।

नवागढ़ राछा भाठा अंबेडकर चौक के पास कांग्रेस जनो द्वारा सभा मे कहा गया कि प्रदेश की भाजपा की विष्णु देव सरकार के द्वारा चौथी बार फिर से आम जनता के जेब में डाका डालने का काम करते हुए बिजली बिल की दरों में बेतहाशा बढ़ोतरी कर दिया है जिसके तहत घरेलू उपभोक्ता के लिए 10से 20पैसा प्रति यूनिट गैर घरेलू उपभोक्ता के लिए 25पैसा प्रति यूनिट बढ़ोतरी के साथ किसानों के कृषि विद्युत दर में भी 50पैसा प्रति यूनिट की बढ़ोतरी एवं बिजली कटौती के आरोप लगाते हुए आज विघुत मंडल कार्यालय का घेराव किया गया । कार्यक्रम में प्रदेश पंचायती राज संगठन के प्रदेश सयोंजक दिनेश शर्मा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद कश्यप जिला पंचायत सदस्य ज्योति किशन खूंटे, गोविंद खरसन,जितेंद्र कश्यप, अब्दुल वहाब,कांति देवी केशरवानी शाहिद शेख ,श्याम बर्मन, राजू साहू,डालेश्वर साहू,मनोहर प्रधान, प्रदीप कश्यप, श्री राम गोंड,राकेश चंद्रा ,गोविंद खरसन सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल रहे।

कश्यप,भुनेश्वर केशरवानी सहित कई कांग्रेस नेताओं ने सभा को सम्बोधित किया आज की इस विघुत मंडल की घेराव कार्यक्रम में बसंत सिंह पवार संतोष साहू,संगीता यादव , वाजिद खान ,दिलदार खान, पवन देवांगन, नुतन देवांगन ,रविन्द्र केशरवानी,शाहरुख खान, पुष्पराज रात्रे, गोविंद केशरवानी ,विक्रम कोसले इतवारी

जमीन विवाद को लेकर फरसे से महिला पर प्राण घातक हमला के आरोपी गिरफ्तार

जांजगीर चांपा / जमीन विवाद को लेकर महिला पर फरसे से प्राणघातकहमला के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है । मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी दोहर दास निवासी भैंसदा थाना नवागढ़ के द्वारा थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज किराया की दिनांक 16 जुलाई 2025 को यह अपने ससुराल डूडगा से जांजगीर गया था । उसी रात्रि 11 बजे इसका बड़ा भाई गिरधरलाल सूर्यवंशी ने फोन कर बताया कि गांव का हीरेंद्र तरुण घर अंदर घुस कर तेरी भाभी को फरसे से मार दिया है । खबर सुनते ही अपने दोस्त नागेंद्र के साथ पहुंचा तब खून से लतपथ हालात मे भाभी को ईलाज कराने के लिए लेकर जा रहे थे। अपने भैया से पूछने पर बताया कि 16 जुलाई 2025 के रात्रि करीबन 9-10 बजे के बीच गांव का हीरेंद्र घर आकर दरवाजा खट खटाने लगा , दरवाजा खोलने पर हिरेंद्र अपने हाथ में लोहे के फरसा रखा हुआ था और बोल रहा था कि तुम मुझे 33 डिसमिल जमीन नहीं बेचे हो किसी और को बेच दिए हो । मै तुमको नहीं छोड़ूंगा और जान से मार दूंगा तभी तुम्हारी भाभी बीच में आई तो हिरेंद्र ने अपने हाथ में रखे फरसे से मार दिया जिससे सिर पर चोट आई और खून निकल रहा है । शाम को भी आरोपी के द्वारा जमीन को मुझे दो नहीं तो में तुम लोगों को जान से मार दूंगा बोलकर धमकी देकर गया था । उक्त रिपोर्ट पर थाना नवागढ़ में अपराध क्रमांक 305/25 धारा 109(1) बीएनएस कायम किया गया। पुलिस अधीक्षक जांजगीर चांपा विजय कुमार पाण्डेय आईपीएस द्वारा प्रकरण में तत्काल कार्यवाही के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कुमार कश्यप एवं उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय जांजगीर विजय कुमार पैकरा के मार्गदर्शन मे आरोपी हिरेंद्र तरुण भैंसदा थाना नवागढ़ को ग्राम खोखरा तरफ से पकड़ा । उससे पूछताछ कर मेमोरेंडम कथन लिया गया तो घटनाकारीत करना जुर्म स्वीकार किए एवं घटना में प्रयुक्त एक लोहे का फरसा को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है। उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक अशोक वैष्णव थाना प्रभारी नवागढ़, निरीक्षक सागर पाठक साइबर सेल प्रभारी, साइबर टीम सउनि विवेक सिंह, प्र.आर. मनोज तिग्गा, आर. सहबाज खान, गिरीस कश्यप, प्रदीप दुबे, माखन साहू, श्रीकांत सिंह का सराहनीय योगदान रहा।

ठेकेदारी प्रतिस्पर्धा के कारण हत्या कर लटकाया फांसी में

सारागांव पुलिस एवं सायबर टीम के हत्थे चढ़े दोनो आरोपी

जांजगीर चांपा / ठेकेदारी प्रतिस्पर्धा के चलते हत्या कर फांसी का नाम देने वाले दोनों आरोपीयों को सारागांव पुलिस एवं सायबर पुलिस ने धर दबोचा है । मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि गत 17 जुलाई 2025 को थाना सारागांव को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम कमरीद के निवासी कीर्तन गबेल के नव निर्मित मकान में किराये से रहने वाले मृतक प्रेमलाल पाण्डेय उम्र 62 वर्ष निवासी बीरसिंगपुर जिला शहडोल (म.प्र.) का शव फांसी के फंदे में झुलते मिला है । खबर प्राप्त होने पर थाना सारगांव पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर जाकर शव का निरीक्षण कर जांच पंचनामा कार्यवाही में लिया गया।

पुलिस अधीक्षक जांजगीर चांपा विजय कुमार पाण्डेय आईपीएस के निर्देशन में मर्ग प्रकरण की जांच को गंभीरता से लेते हुए थाना सारागांव पुलिस द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण करने पर प्रथम दृष्टया मृतक की मृत्यु संदेहास्पद होने से घटना की सूचना से जिले के वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। प्रकरण में हत्या की आशंका होने से

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये पुलिस अधीक्षक जांजगीर चांपा के द्वारा मामले की जांच एवं अज्ञात आरोपी की तत्काल पतासाजी एवं अविलंब गिरफ्तारी हेतु जिला सायबर सेल की टीम को आदेशित करने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जांजगीर उमेश कुमार कश्यप के कुशल मार्गदर्शन तथा एसडीओपी चांपा यदुमणि सिदार के नेतृत्व में सायबर सेल टीम ने मौके पर पहुंचकर थाना सारागांव प्रभारी के साथ समन्वय स्थापित कर घटना स्थल निरीक्षण एवं मृतक से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पहलु को बारिकी से निरीक्षण एवं तकनीकि जानकारी एकत्र किए । आरोपी भीष्मनारायण उर्फराहुल एवं हेमराज पटेल दोनों को हिरासत में लेकर घटना के संबंध में बारिकी से पुछताछ करने पर गोलमोल जवाब देने से थाना सारागांव एवं सायबर पुलिस द्वारा मनोवैज्ञानिक एवं कड़ाई से पुछताछ करने पर घटना के संबंध में बताया कि मृतक प्रेमलाल पाण्डेय द्वारा ठेकेदारी कार्य के प्रतिस्पर्धा एवं वर्चस्व बनाने के लिये आये दिन मारने की धमकी देकर अश्लील गाली गलौच करता था । मृतक द्वारा घटना के एक दिन पहले अश्लील गाली गलौच देकर जान से मारने की धमकी दिया था जिस कारण दोनो आरोपियों द्वारा मृतक को सबक सिखाने एवं हत्या करने की योजना बनाकर दिनांक 16 जुलाई 2025 की रात्रि में योजनाबद्ध तरीके से एक राय होकर राहुल के मो.सा. से मृतक के किराये के घर से एक कि.मी. दूर अपने वाहन को खडा कर पैदल - पैदल मृतक के घर कमरे में गये । वहां उन्होने बड़ा गुण्डा बनता है हमें मारेगा कहकर हाथ झापड़ से मारपीटकिए और मृतक के कमरे में रखे एक नायलोन के रस्सी से फंद्दा बनाकर मृतक के गले में डालकर खींचा गया जिससे मृतक की पलंग से नीचे गिरकर मृत्यु हो गई , तब दोनो आरोपीयो द्वारा पुलिस से बचने के लिये हत्या को आत्महत्या का स्वरूप देने के लिए कमरे के सीढी में रस्सी बांधकर मृतक को फांसी से टांग दिये बताया। इस कबूलनामा के बाद आरोपियों की विधिवत मेमोरेण्डम कथन लेकर मामले में गिरफ्तारी की कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।

नगर पालिका जांजगीर नैला द्वारा...... आवारा पशुओं को सड़क से हटाए जाने की कार्यवाही.....

जांजगीर चांपा नगर पालिका परिषद जांजगीर नैला क्षेत्र अंतर्गत नगर के मुख्य मार्ग जैसे कचहरी चौक से कलेक्ट्रेट चौक, कचहरी चौक से नैला ,कचहरी चौक से नेताजी चौक ,नेताजी चौक से बनारी रोड, नेताजी चौक से बीटीआई चौक तक एवं कचहरी चौक से खोखरा चौक तक में सड़क पर आवारा मवेशियों के जमावाड़ा होने के कारण आवागमन में बाधा उत्पन्न कर रहे , जिसे निकाय की टीम के द्वारा समस्त मवेशियों को हटाए जाने की कार्यवाही की जा रही है, जिससे आवागमन सुगम होगा एवं दुर्घटना की संभावना में कमी आवेगीद्य नगर पालिका ने आम जनता सेअपील की है कि वे सड़क से मवेशियों को हटाए जाने में सहयोग प्रदान करें तथा पशु पालकों से अनुरोध है कि अपने पशुओं को घर में बांधकर रखें अन्यथा की स्थिति में जुर्माना की कार्यवाही की जावेगी।

वन महोत्सव कार्यक्रम-2025 का हुआ आयोजन

जिला पंचायत अध्यक्ष, कलेक्टर सहित जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों ने एक पेड़ माँ के नाम किया पौधारोपण

11वीं बटालियन पुटपुरा में 23 हेक्टेयर क्षेत्र में 25,300 पौधे लगाए गए

जांजगीर-चांपा / वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के तत्वावधान में आज 11वीं बटालियन पुटपुरा परिसर में वन महोत्सव कार्यक्रम-2025 का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सत्यलता आनंद मिरि, कलेक्टर श्री जन्मेजय महोबे, डीएफओ श्री हिमांशु डोंगरे, कमांडेंट श्री विमल बैस, जिला पंचायत सदस्य सुश्री आशा साव, श्रीमती उमा राजेन्द्र राठौर, श्री अमर सुल्तानिया, श्री आनंद मिरि सहित जनप्रतिनिधि एवं उपवनमंडल अधिकारी, वनपरिक्षेत्र अधिकारी, अधिकारी-कर्मचारियों ने एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान के तहत पौधारोपण किया।

कलेक्टर श्री महोबे ने 11वीं बटालियन पुटपुरा में किये गये 23 हेक्टेयर में 25,300 पौधरोपण अभियान की सराहना की। कलेक्टर ने सभी नागरिकों से अपने आस-पास अधिक से अधिक पेड़-पौधे लगाने की अपील की। उन्होंने कहा कि एक पेड़ माँ के नाम अभियान का उद्देश्य वृक्षारोपण एवं भावनात्मक जुड़ाव के माध्यम से प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी विकसित करना है। उन्होंने लगाए गए पौधों की नियमित देखभाल व निगरानी सुनिश्चित करने कहा। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सत्यलता आनंद मिरि एवं जनप्रतिनिधियों ने अधिक से अधिक पौधे लगाने एवं उसकी देखभाल करने की अपील की।

वनमंडलाधिकारी श्री हिमांशु डोंगरे ने कहा कि 11वीं बटालियन पुटपुरा में 23 हेक्टेयर क्षेत्र में चरणबद्ध 25,300 पौधों का रोपण किया गया। उन्होंने सभी नागरिकों, स्वयं सेवी संगठनों, जनप्रतिनिधियों से पौधरोपण करने और उसकी देखभाल करने की अपील की। उन्होंने कहा कि पौधरोपण से हम न केवल पर्यावरण को सुरक्षित करते हैं, बल्कि भावी पीढ़ियों को स्वच्छ हवा और स्वस्थ वातावरण का उपहार देते हैं। इस अवसर पर नीम, सागौन, महोगनी, आम, अर्जुन, करंज, अशोक, आंवला सहित विभिन्न औषधीय एवं फलदार पौधे लगाये गये।

जिला पंचायत सदस्यों का आधारभूत प्रशिक्षण संपन्न

0 सदस्यों को अधिकार, कर्तव्य एवं विकास योजनाओं की दी गई जानकारी

महासमुंद, जिला पंचायत महासमुंद के सभा कक्ष में जिला पंचायत सदस्यों के लिए एक दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में नव निर्वाचित एवं वर्तमान सदस्यों को पंचायत से जुड़े अधिकारों, कर्तव्यों तथा विकास योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान किया गया। प्रशिक्षण में उपसंचालक पंचायत श्रीमती दीप्ति साहू द्वारा 73वें संविधान संशोधन, जिला पंचायत सदस्यों की भूमिका, सामान्य सभा एवं स्थाई समिति की प्रक्रिया, 15वें वित्त आयोग, जिला पंचायत विकास योजना, सतत विकास लक्ष्य एवं इससे संबंधित 9 प्रमुख थीमों के बारे में विस्तारपूर्वक मार्गदर्शन दिया गया। प्रशिक्षण में जिला पंचायत के लेखाधिकारी गोपेश कुमार होता ने बजट निर्माण एवं प्रबंधन की प्रक्रिया की जानकारी दी। वहीं प्रभारी जिला ऑडिटर अशोक चंद्राकर ने पंचायतों में कर व्यवस्था और ऑडिट प्रक्रिया पर प्रकाश डाला। सहायक परियोजना अधिकारी मनोज गुप्ता ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत नागरिकों को मिलने वाले अधिकारों और पंचायत की जवाबदेही से जुड़ी जानकारियाँ साझा कीं। प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला पंचायत सदस्यगण श्रीमती रामदुलारी सिंह, श्रीमती देवकी पटेल, श्रीमती देवकी पुरुषोत्तम दीवान, श्रीमती जगमोती भोई, श्रीमती कुमारी भास्कर, जुगनू जागेश्वर चंद्राकर, नैन पटेल, मोक्ष कुमार प्रधान, करण सिंह दीवान एवं लोकनाथ बारी उपस्थित रहे।

पुलिस अधिकारी कर्मचारी की समस्याओं के निराकरण हेतु पुलिस दरबार का आयोजन

पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज डॉ. संजीव शुक्ला द्वारा पुलिस लाइन जांजगीर, पुलिस अधीक्षक कार्यालय का किया गया वार्षिक निरीक्षण

जांजगीर चांपा /

आज दिनांक 18 जुलाई 2025 को पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज बिलासपुर के द्वारा जिला जांजगीर-चापा का वार्षिक निरीक्षण किया गया जिसमें सर्वप्रथम पुलिस महानिरीक्षक के द्वारा रक्षित केंद्र में परेड की सलामी ली गई तत्पश्चात् परेड का निरीक्षण किये। परेड निरीक्षण में पुलिस महानिरीक्षक महोदय द्वारा प्रत्येक अधि/कर्म. के टर्नआउट का निरीक्षण एवं टोलीवार परेड कराया गया, जिसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले को नगद पुरस्कार से पुरस्कृत भी किया गया। परेड समाप्ति उपरान्त रक्षित केन्द्र जांजगीर में जिले के पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण हेतु पुलिस दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस महानिरीक्षक महोदय द्वारा अधिकारियो/कर्मचारियों से रूबरू हुए एवं समस्याओं के निराकरण करने का आश्वासन दिये साथ ही थाना चौकी में पदस्थ अधि/कर्म को थाना में आने वाले पीड़ितों एवं शिकायतकर्ताओं की समस्याओं का उचित निराकरण एवं अच्छा व्यवहार करने हेतु निर्देशित किया गया।

वाहन शाखा, आर्म्स स्टोर शाखा का निरीक्षण - पुलिस महानिरीक्षक द्वारा पुलिस सम्मेलन के पश्चात् रक्षित केन्द्र के समस्त शाखाओं का निरीक्षण किया गया, जिसमें वाहन शाखा एवं सभी वाहनों तथा दस्तावेजों का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। स्टोर शाखा का निरीक्षण कर उपलब्ध सामग्रियों का सही तरीके से रख रखाव करने एवं उसके सही समय पर वितरण करने हेतु निर्देशित किया गया। इसी प्रकार आर्म्स शाखा का भी निरीक्षण कर हथियारों को सुरक्षित रखने तथा नियमित रूप से साफसफाई करने के निर्देश दिये गए।

पुलिस अधीक्षक कार्यालय का निरीक्षण - पुलिस महानिरीक्षक द्वारा निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक कार्यालय का भी निरीक्षण किया गया जिसमें कार्यालय के समस्त शाखाओं का निरीक्षण कर शाखाओं के कार्यों की जानकारी ली, जिसमें कार्यालय में संचारित किये जा रहे पुलिस अधि/कर्म. की सेवा पुस्तिका की जांच कर आवश्यक प्रविष्टिओं को पूर्ण करने के निर्देश दिये, साथ ही अनुकम्पा नियुक्ति, लंबित पेंशन प्रकरणों, विभागीय भविष्य निधि, जिले में चल रहे निर्माण कार्यों, बजट की स्थिति, न्यायालय संबंधी प्रकरणों, निलंबित अधि/कर्म, तथा उनके अपील अवकाश निराकरण आदि के संबंध में जानकारी ली तथा थाना चैकी में पदस्थ कर्मचारियों से प्राप्त आवेदनों पर त्वरित कार्यवाही करने तथा अनावश्यक लंबित नहीं रखने के निर्देश दिये गयेद्व

जिले के सड़क सुरक्षा मितानो का सम्मेलन कार्यक्रम - जिले के सड़क सुरक्षा मितानो का आनंदमधाम रिसार्ट अमरताल अकलतरा में सम्मेलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सड़क सुरक्षा मितानों को दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल जांजगीर के चिकित्सकों के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। इसके बाद पुलिस महानिरीक्षक महोदय द्वारा सड़क सुरक्षा मितानो को बताया कि ''राहवीर योजना'' एक स्वैच्छिक नागरिक सहायता कार्यक्रम है। इसमें कोई भी आम व्यक्ति जो दुर्घटना के बाद घायल को सुरक्षित नजदीकी अस्पताल तक पहुंचाता है, उसे 25 हजार रूपए तक की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। योजना का यह भी उद्देश्य है कि ऐसे नागरिकों को किसी तरह की कानूनी कार्यवाही या पूछताछ का सामना न करना पड़े।

निरीक्षण कार्यक्रम दौरान पुलिस अधीक्षक जांजगीर विजय कुमार पाण्डेय आईपीएस , अति. पुलिस अधीक्षक जांजगीर उमेश कुमार कश्यप, अति. पुलिस अधीक्षक यातायात उदयन बेहार, डीएसपी अजाक जितेन्द्र खुंटे, एसडीओपी चाम्पा यदुमणि सिदार, डीएसपी (मुख्यालय) विजय पैकरा, एसडीओपी जांजगीर प्रदीप कुमार सोरी, डीएसपी श्रीमती सत्यकला रामटेके, रक्षित निरीक्षक प्रदीप कुमार जोशी तथा जिले के थाना चौकी प्रभारीगण उपस्थित रहे।

खास खबर

जिले में छ जिले में छग व्यवसायिक योजित होने वाले परीक्षाओं के लिए उप पुलिस अधीक्षक होंगे जिला पुलिस नोडल अधिकारी

कोरबा, छत्तीसगढ़ व्यवसायिक मंडल रायपुर द्वारा जारी आदेश के परिपालन में कलेक्टर श्री अजीत वसंत द्वारा जिले में छ0ग0 व्यवसायिक मंडल द्वारा जिले में आयोजित होने वाले आगामी परीक्षाओं के सुचारू संचालन हेतु उप पुलिस अधीक्षक श्री बेनेडिक्ट मिंज मोबाइल नंबर 8839253729 को आगामी आदेश पर्यन्त जिला पुलिस नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

आईटीआई करतला में प्रवेश के लिए आनलाइन आवेदन 23 तक

कोरबा, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था करतला जिला कोरबा में संचालित एकवर्षीय पाठ्यक्रम व्यवसाय-कोपा, मेकेनिक डीजल और वेल्डर तथा द्विवर्षीय पाठ्यक्रम व्यवसाय विद्युतकार एवं फिटर में रिक्त स्थानों में प्रवेश के लिए 23 जुलाई 2025 तक आवेदन किया जा सकता है। प्रवेश हेतु इच्छुक आवेदक संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण द्वारा जारी विभागीय वेबसाइट- cgiti.admissions.nic.in पर जाकर आनॅलाईन आवेदन कर सकते है। संस्था के अधीक्षक से प्राप्त जानकारी के अनुसार पूर्व के आवेदक जो अगली चरण में शामिल होना चाहते हैं उन्हें अपने लागिन आईडी एवं पासवर्ड से लागिन कर अपनी प्रोफाइल संस्था/व्यवसाय के प्राथमिकता क्रम का चयन पुनः किया जाना अनिवार्य होगा। अन्यथा उन्हें अगले चरण में शामिल नहीं किया जायेगा।

भारतीय वायु सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाईन आवेदन 31 तक आमंत्रित

कोरबा, भारतीय वायुसेना में भर्ती हेतु कार्यालय भोपाल द्वारा छत्तीसगढ़ के अविवाहित पुरूष एवं महिला आवेदकों से अग्निवीर वायु वर्ष 2026 हेतु ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये गये हैं। भारतीय वायुसेना में अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाईन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है जो 31 जुलाई 2025 रात्रि 11.00 बजे तक खुली रहेगी। इसके लिए ऑनलाईन फार्म एवं विस्तृत जानकारी भारतीय वायुसेना के वेबसाईट www.agnipathvayu.cdac.in पर उपलब्ध है। ऐसे आवेदक जिनका जन्म 02 जुलाई 2005 एवं 02 जनवरी 2009 के बीच हुआ है और जो 102 या समकक्ष परीक्षा विज्ञान समूह जैसे - गणित भौतिकी एवं अंग्रेजी में किसी मान्यता प्राप्त केन्द्रीय राज्य या केन्द्र शासित राज्य बोर्ड से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ जिसमें अंग्रेजी विषय में 50 प्रतिशत अंक हो। 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स इंजीनियरिंग जैसे इलेक्ट्रिकल/ इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाईल, कम्प्यूटर साइंस, इस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, इंफोरमेशन टेक्नोलॉजी इत्यादि। मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा राज्य, केन्द्र शासित राज्य से 50 प्रतिशत अंकों के साथ तथा जिसमें इंटरमिडिएट/मैट्रिकुलेशन में अंग्रेजी विषय में 50 प्रतिशत अंक हो/ 2 वर्षीय व्यावसायिक कोर्स हो तथा जो छत्तीसगढ़ का निवासी है। ऑनलाईन पंजीयन कर सकते हैं।

एग्रीस्टेक पोर्टल में किसानों का फार्मर आईडी पंजीयन कराना अनिवार्य

0 पोर्टल में फार्मर आईडी पंजीकृत किसान ही सोसाइटी में विक्रय कर पाएंगे धान

0 पोर्टल में पंजीयन के माध्यम से किसान समर्थन मूल्य पर पारदर्शिता के साथ आसानी से कर सकेंगे धान विक्रय

किसान 30 अगस्त 2025 तक एग्रीस्टेक पोर्टल में करा सकते है फार्मर आईडी पंजीयन

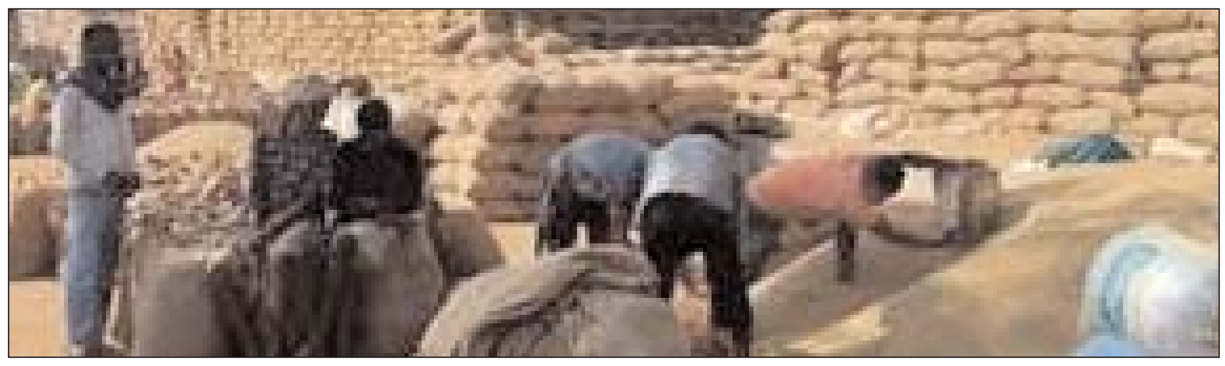

कोरबा आगामी धान खरीदी खरीफ वर्ष 2025-26 के लिए राज्य शासन ने एग्रीस्टेक प्रोजेक्ट के अंतर्गत एग्रीस्टेक पोर्टल में फार्मर आईडी किसान पंजीयन को सभी किसानों के लिए अनिवार्य कर दिया है। इसके तहत प्रदेश भर के सभी किसानों को एग्रीस्टेक पोर्टल में पंजीकृत किया जाएगा जिससे किसान समर्थन मूल्य पर पारदर्शिता के साथ आसानी से धान विक्रय कर पायेंगे।

जिले में एग्रीस्टेक पोर्टल पर फार्मर आईडी किसान पंजीयन की अंतिम तिथि 30 अगस्त 2025 निर्धारित की गई है। अब तक जिले के कुल 56,801 किसानों ने फॉर्मर आईडी बनवा लिया हैं। जिसमें अजगरबहार तहसील में 1474, तहसील बरपाली में 10555, कोरबा में 2971, करतला में 4108 , भैंसमा में 4151, कटघोरा में 3863, दर्री में 1035, दीपका में 3837, पाली में 9008, हरदीबजार में 5547, पोड़ी उपरोड़ा में 6539 एवं पसान 3713 किसानों ने फार्मर आईडी पंजीयन करा लिया है।

अपंजीकृत किसान पीएम सम्मान निधि से हो सकते है वंचित

फसल बीमा कराने हेतु एग्रीस्टेक पोर्टल में फार्मर आईडी किसान पंजीयन अनिवार्य किया गया है तथा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की आगामी किस्त का हस्तांतरण फार्मर आईडी, किसान कार्ड के आधार पर किये जाने के निर्देश पीएम किसान सम्मान निधी योजना में हैं। जिले के 1,42, 424 किसानों का पंजीयन है, इसमें से अब तक केवल 56801 सहित 39.88 प्रतिशत किसानों ने एग्रीस्टेक पोर्टल में फार्मर आईडी किसान पंजीयन कराया है। किसानों द्वारा पोर्टल में फार्मर आईडी नही बनवाने की स्थिति में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के किस्त से वंचित हो सकते हैं।

स्वयं या समिति व सीएससी के माध्यम से करा सकते है पंजीयन

एग्रीस्टेक पोर्टल पर किसान स्वयं पंजीयन कर सकते हैं अथवा अपने क्षेत्र के सहकारी समिति अथवा निकटतम लोक सेवा केन्द्र (सीएससी) में जाकर पंजीयन करा सकते हैं। फॉर्मर आईडी बनवाने के लिए किसान को अपने सभी कृषि भूमि का बी-1, ऋण पुस्तिका, आधार कार्ड और आधार से लिंक मोबाईल नम्बर (जिसमें आधार सत्यापन ओटीपी प्राप्त होती हो) की आवश्यकता होगी।

किसान को मिलेगा 11 अंकों की विशिष्ट पहचान -

पंजीयन पश्चात् किसानों को आधार नंबर के जैसे 11 अंकों की एक यूनिक फॉर्मर आईडी (विशिष्ट किसान आईडी) मिलेगी जिससे किसान डिजिटल रूप से अपनी पहचान प्रमाणित कर सकेंगे। एग्रीस्टेक भारत सरकार द्वारा विकसित एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसका उद्देश्य भारतीय कृषि क्षेत्र को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना है। यह किसानों के लिए एक व्यापक डेटाबेस बनाने पर केंद्रित है जिसमें उनकी पहचान, भूमि रिकॉर्ड , वित्तीय जानकारी, फसल की जानकारी और बीमा इतिहास शामिल है। एग्रीस्टेक पोर्टल में किसानों को प्राथमिक सहकारी समितियों तथा कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से पंजीकरण करने की सुविधा प्रदान करता है। एग्रीस्टेक पोर्टल छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है जो उन्हें डिजिटल रूप से सशक्त बनाने और उनकी आय बढ़ाने में मदद करेगी।

एग्रीस्टेक पोर्टल के माध्यम से किया गया फार्मर आईडी पंजीयन ई-केवाईसी युक्त होता है। जिससे दोहराव की संभावना समाप्त हो जाती है और किसानों की वास्तविक पहचान सुनिश्चित होती है। राज्य शासन द्वारा यह व्यवस्था इसलिए की जा रही है ताकि कृषकों को शासकीय योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से मिल सके। इसके लिए राज्य शासन द्वारा एकीकृत किसान पोर्टल विकसित किया गया है। सभी प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों को निर्देशित किया गया है कि वे एकीकृत किसान पोर्टल के माध्यम से किसानों का नवीन पंजीयन एवं फसल रकबे का संशोधन कार्य प्राथमिकता के आधार पर संपादित करें। जिसमें पंजीयन की प्रक्रिया प्रतिवर्ष 01 जुलाई से 31 अक्टूबर तक संचालित की जाती है। इस वर्ष भी खरीफ मौसम के लिए यह प्रक्रिया निर्धारित अवधि में पूर्ण की जाएगी।

बिहान योजना अंतर्गत जिला स्तरीय बैंकर्स प्रशिक्षण सह कार्यशाला का हुआ आयोजन

बैंकर्स और फील्ड स्टाफको दी गई वित्तीय पहलुओं की विस्तृत जानकारी

कोरबा बिहान योजना के तहत मंगलवार को जिला पंचायत कोरबा के सभागार में जिला स्तरीय बैंकर्स प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया कार्यशाला में लगभग 100 प्रतिभागियों ने सक्रिय सहभागिता दर्ज कर कार्यशाला को सफल बनाया। कार्यशाला में बैंकर्स, बीपीएम, एडीईओ, एरिया कोऑर्डिनेटर, पीआरपी, एफएलसीआरपी, बैंक सखी तथा अन्य फील्ड स्टाफ शामिल हुए।

कार्यशाला की अध्यक्षता मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कोरबा श्री दिनेश कुमार नाग ने की। कार्यक्रम में सहायक परियोजना अधिकारी सुश्री इंदिरा भगत, एनआरपी श्री गगन बिहारी भुयान, सा-धन स्टेट हेड सुश्री नियति धुर्वे, डीडीएम नाबार्ड श्री संजीव प्रधान, एलडीएम श्री कृष्णा भगत, डीपीएम (प्रबंधन) श्री जॉन प्रेरा मिंज, डीपीएम (वित्तीय समावेशन) श्री चिराग ठक्कर, तथा डीएच सा-धन श्री प्रणव देवांगन सहित अन्य जिला स्तरीय स्टाफ की उपस्थिति रही।

कार्यशाला में श्री गगन बिहारी भुयान द्वारा बिहान योजना की अवधारणा, समूह क्रेडिट लिंकेज, इंटरप्राइज फाइनेंस, बीसी सखी मॉडल, बीमा योजनाएं, एनपीए का निराकरण, और सीबीआरएम कमेटी की भूमिका जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत जानकारी दी गई। इसके साथ ही वित्तीय साक्षरता, बैंक लिंकेज, डिजिटल बैंकिंग, एवं आवश्यक दस्तावेजीकरण जैसे व्यावहारिक विषयों पर भी प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया गया। सीईओ श्री दिनेश नाग ने कार्यशाला में उपस्थित पीआरपी एवं एफएलसीआरपी से प्रशिक्षित विषयों पर संवाद किया और बैंकर्स को समयबद्ध तरीके से प्रकरणों के निराकरण के निर्देश दिए। कार्यशाला का प्रमुख उद्देश्य बैंकिंग से जुड़े फील्ड स्टाफ और बैंकर्स की क्षमताओं का निर्माण करना तथा उन्हें वित्तीय पहलुओं की बेहतर समझ प्रदान कर बिहान योजना को प्रभावशाली ढंग से जमीनी स्तर पर कार्य करना है। इस कार्यशाला न केवल बैंकों और बिहान टीम के बीच समन्वय को सुदृढ़ करने की दिशा में एक प्रभावी कदम रहा, बल्कि इससे जमीनी स्तर पर वित्तीय समावेशन और महिला सशक्तिकरण को भी बल मिलेगा।

महिलाओं ने की शराब बंदी की मांग

कोरबा । शराब से गांव का माहौल खराब हो रहा है। जिसे लेकर श्यांग थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत बासीन की महिलाओं ने गांव में अवैध शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। इसे लेकर महिलाओं ने कलेक्टर को जनदर्शन में ज्ञापन सौंपा है।

कलेक्टर को समस्या से अवगत कराया है। महिलाओं ने बताया कि छह माह पहले गांव को शराब मुक्त गांव बनाने को लेकर जनप्रतिनिधियों में सहमति बनी थी, लेकिन अब भी अवैध शराब का कारोबार चल रहा है। इसका गांव के बच्चों पर कुप्रभाव पड़ रहा है। शराब के नशे में कई लोग आपस में विवाद करते हैं। इससे महिलाओं को परेशानी हो रही है। इसका बच्चों के पढ़ाई पर भी असर पड़ रहा है। शाम होने के बाद युवती और महिलाओं को घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। परेशान महिलाओं ने अवैध शराब विक्रेता करने वालों पर कार्रवाई की मांग की है।

वर्मी कंपोस्ट खाद का भुगतान लटका

ग्राम पंचायत बरपाली की स्व सहायता समूह की महिलाओं ने वर्मी कंपोस्ट का भुगतान नहीं मिलने से परेशान हैं। समूह ने इसकी शिकायत कलेक्टर जनदर्शन में की है।

आउट सोर्सिंग कंपनी कलिंगा एक बार फिर सुर्खियों में, बिना सूचना व नोटिस काम बंद किए जाने व वेतन भुगतान को लेकर कर्मियों ने की शिकायत

कोरबा आउट सोर्सिंग कंपनी कलिंगा एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार बिना सूचना व नोटिस काम बंद किए जाने को लेकर कर्मियों ने शिकायत की है। साथ ही कर्मियों को वेतन भुगतान नहीं किए जाने से उन्हें बेरोजगार होकर आर्थिक परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। इसे लेकर उन्होंने मानिकपुर जीएम और प्रशासन से शिकायत की है। मांग पूरी नहीं होने पर 16वें दिन आंदोलन की चेतावनी दी है।

मामले की शिकायत कलिंगा कमर्शियल कार्पोरेशन लिमिटेड कंपनी के चालकों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर की है। शिकायत पत्र में कहा गया है कि एसईसीएल मानिकपुर परियोजना में नियोजित कंपनी कलिंगा कमर्शियल कार्पोरेशन लिमिटेड कंपनी, जो ओवर बर्डन का पिछले दो साल से कार्य करते आ रही है। जबकि मानिकपुर साईट का काम 1095 दिन का वर्क आर्डर कलिंगा कंपनी को मिला है। कंपनी द्वारा बिना सूचना दिये वर्करों से 18 मई 2025 को कार्य को बंद कर दिया गया। जबकि कोई भी नियोजित ठेका कंपनी कार्य बंद करने के तीन माह पहले वर्करों को नोटिस देता है, जो कि इस कंपनी ने नही किया। इसके पूर्व 26 मई 2025 को सभी वर्करों के द्वारा एसईसीएल प्रबंधन को आवेदन दिया गया था, कि जब तक कंपनी का टेण्डर है दिसम्बर 2025 तक उनके वेतन का भुगतान किया जाए। आज दिनांक तक एसईसीएल प्रबंधक की ओर से हमें कोई जवाब नहीं मिला है। कलिंगा कंपनी द्वारा उन्हें बिना सूचना दिए कार्य को बंद कर दिया गया।

कलेक्टर ने किया बाल सुधार गृह और प्रधानमंत्री आवास दादर खुर्द का निरीक्षण

0 बाल सुधार गृह को पूर्ण कर महिला एवं बाल विकास विभाग को हैंड ओव्हर करने के दिए निर्देश

0 पीएम आवास योजना अन्तर्गत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों का सूची बनाने और बरसात के बाद शिफ्टिंग के दिये निर्देश

कोरबा, कलेक्टर श्री अजीत वसंत ने आज बाल सुधार गृह कोहड़िया और प्रधानमंत्री आवास योजना अन्तर्गत दादर खुर्द में बने मकान का निरीक्षण किया। उन्होंने निगम आयुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय को निर्देशित किया कि बाल सुधार गृह के एक ब्लाक को 15 दिवस के भीतर एवं शेष तीन ब्लाक को एक माह के भीतर पूर्ण कर महिला एवं बाल विकास विभाग को हैंड ओव्हर करें। कलेक्टर ने बाल सुधार गृह में भवन तक पूर्व में पहुंच मार्ग नहीं होने की बात सामने आने के पश्चात पहुंच मार्ग बनाने के निर्देश दिये थे। निरीक्षण के दौरान उन्होने निगम आयुक्त से सड़क से भवन तक बनाये गये पहुंच मार्ग की भी जानकारी ली। कलेक्टर ने ग्राम दादर खुर्द में प्रधानमंत्री आवास योजना अन्तर्गत निर्मित मकानों का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्देशित किया कि योजना के तहत आवास आवंटियों को बरसात के पश्चात शिफ्टिंग किया जाना सुनिश्चित किया जाये। कलेक्टर ने निर्देशित किया कि जो आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति हैं और पैसा जमा नहीं कर सकते हैं, उनकी सूची बना ली जाये। ताकि ऐसे जरूरतमंद आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों पर आवास आबंटन के संबंध में विचार किया जा सके। इस दौरान निगम के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

मेडिकल कालेज में नवजात शिशुओं के उपचार में नहीं आयेगी समस्या

0 एसएनसीयू में छह बिस्तर और बढ़ेंगे, वर्तमान में है 12 बेड की सुविधा

0 पीएचसी कोरबा में पोर्टेबल एक्सरे की भी होगी सुविधा

0 जिला प्रशासन की पहल पर सीएसआर मद में एनटीपीसी से मिली एक करोड़ 05 लाख राशि की स्वीकृति

कोरबा । जिले में स्थित स्वर्गीय बिसाहू दास महंत स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कोरबा में जल्द ही स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि होने वाली है। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर कलेक्टर श्री अजीत वसंत ने एनटीपीसी को सीएसआर मद से स्वास्थ्य सुविधा हेतु उपकरण और सामग्री के लिए प्रस्ताव प्रेषित किया था। प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात एनटीपीसी ने मेडिकल कालेज में नवजात शिशुओं के उपचार की सुविधा में वृद्धि के लिए और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोरबा में एक्सरे की सुविधा के लिए एक करोड़ पांच लाख की राशि स्वीकृत की है। उक्त राशि की स्वीकृति से मेडिकल कॉलेज के शिशु रोग विभाग में बिस्तरों की संख्या 12 से बढ़कर 18 हो जाएगी।

वहीं पीएचसी कोरबा में पोर्टेबल एक्सरे मशीन की व्यवस्था होने से यहां आने वाले मरीजों को एक्सरे जांच के लिए निजी अस्पताल नहीं जाना पडेगा।

जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोत्तरी के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किये जा रहे हैं।

इसी कड़ी में स्वास्थ्य विभाग से मांग आई थी कि स्वर्गीय बिसाहू दास महंत स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय के शिशु रोग विभाग में नवजात शिशु ईकाई (एसएनसीयू) में विगत कुछ वर्षों से नवजात शिशुओं की भर्ती में वृद्धि हुई है। जिसकी वजह से बिस्तरों की संख्या कम पड़ रही है। यहां नवजात शिशुओं के उपचार हेतु बिस्तरों की संख्या को 12 से बढ़ाकर 18 करने का प्रस्ताव दिया गया था। ताकि अधिक से अधिक शिशुओं का इलाज हो सके। इसी तरह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोरबा में मरीजों को एक्स-रे की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए भी मांग की गई थी। इसके लिए कुल एक करोड़ पांच लाख की राशि का प्रस्ताव स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिया गया था। कलेक्टर श्री वसंत ने स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव के आधार पर महाप्रबंधक एनटीपीसी को सीएसआर मद से उक्त राशि स्वीकृति हेतु पत्र लिखा था। कलेक्टर द्वारा प्रेषित पत्र के आधार पर एनटीपीसी द्वारा नवजात शिशु ईकाई में आवश्यक उपकरण और सामग्री तथा पोर्टेबल एक्स-रे के लिए एक करोड़ पांच लाख की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है।

बंद ऋतु में वैधानिक मत्स्याखेट रोकने मछली पालन विभाग द्वारा किया जा रहा औचक निरीक्षण

कोरबा मछली पालन विभाग द्वारा जिले में शासन द्वारा घोषित बंद ऋतु 16 जून से 15 अगस्त तक में मत्स्याखेट पर प्रतिबंध है। सहायक संचालक मत्स्य विभाग ने बताया कि अवैधानिक मत्स्याखेट रोकने मछली पालन विभाग द्वारा मंगलवार को हसेदव नदी के जामकछार, घोंसरा, गड़रा (मिडियाकछार) एवं बांगो जलाशय के एतमानगर क्षेत्र में औचक छापेमारी किया गया। इस दौरान गड़रा (मिडियाकछार) में मत्स्याखेट में लगे मछुआरे जाल छोड़कर भागे, जामकछार (पठानघाट) एवं घोंसरा के स्थानीय मछुवारों को चेतावनी दी गई। अवैधानिक मत्स्याखेट किये जाने पर सख्त कार्यवाही की जायेगी। मंगलवार को दिनभर विभाग की टीम अलग-अलग जगहों पर छापामारी कार्यवाही करते रहे। यह कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी। उन्होंने प्रतिबंधित अवधि में नदी-नाले एवं जलाशय में मत्स्याखेट ना करने का आग्रह किया है।

केन्द्रीय मंत्री जोशी से मुलाकात करते हुए मुख्यमंत्री

छत्तीसगढ़ में बांग्लादेशी घुसपैठ पर सियासी घमासान

रायपुर, छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान कर उन्हें देश से बाहर भेजने की प्रक्रिया में तेजी ला रही है। लेकिन इस कार्रवाई को लेकर अब राजनीतिक विवाद भी गहराता जा रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि अगर बंगाली भाषी लोगों पर अत्याचार नहीं रुका, तो इसके गंभीर राजनीतिक परिणाम होंगे। कोलकाता में आयोजित एक रैली में ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि देश भर में बंगाल के श्रमिकों को बांग्लादेशी बताकर उन्हें परेशान किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र और भाजपा बंगालियों के साथ भेदभाव कर रही है। ममता ने चुनौती देते हुए कहा, अगर भाजपा में हिम्मत है, तो मुझे डिटेंशन सेंटर में डालकर दिखाए। अगर बंगालियों को डिटेंशन में भेजने की कोशिश की गई, तो जनता भाजपा को चुनाव में सबक सिखाएगी। इस बयान पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने ममता बनर्जी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि विपक्षी पार्टियों की मंशा देश की जनसंख्या संरचना को प्रभावित करने की है। शर्मा ने दावा किया कि बंगाल से लोग फर्जी आधार कार्ड बनवाकर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं और पूछने पर अपना गांव या जन्मस्थान भी सही से नहीं बता पाते। उन्होंने कहा, उनकी भाषा और बोलने के अंदाज़ से सब साफ़ हो जाता है।

सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाएं हम- डीएसपी ऑफिस परिसर में वृक्षारोपण कर दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश

धमतरी, । पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से आज डीएसपी कार्यालय परिसर धमतरी में पाँच नग अशोक के पौधे रोपित कर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाएं हम जैसे जागरूकता नारों के साथ आमजन को पौधे वितरित कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। डीएसपी सुमीना साहू एवं सुमोनिका मरावी के साथ ही कार्यक्रम में लायनेस क्लब की फाउंडर मेंबर श्रीमती प्रभा रावत, ऑल इंडिया लायनेस क्लब की अध्यक्ष श्रीमती जानकी गुप्ता, उपाध्याय श्रीमती सोना चंदवानी, श्रीमती पूजा रामरख्यानी, श्रीमती शिल्पी महावर, श्रीमती कनक शाह एवं श्रीमती नव्या वाधवानी सहित डीएसपी कार्यालय के सउनि. राकेश मिश्रा, प्रआर. उमाकांत साहू एवं आरक्षक फ़्लेश साहू सहित समस्त स्टॉफ ने वृक्षारोपण के कार्यक्रम को सफल बनाया। यह पहल न केवल हरियाली बढ़ाने की दिशा में एक कदम है, बल्कि आम नागरिकों को प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी का एहसास दिलाने का भी सशक्त माध्यम बन रही है।

डीएपी की कमी, सदन में जमकर हंगामा एवं नारेबाजी

खाद की कमी को लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरा, कालाबाजारी करने का आरोप

कांग्रेस ने घड़ियाली आंसू बहा रहे

गर्भगृह में कांग्रेसजनों ने दिया धरना, स्वयं हुए निलंबित

रायपुर, लोकशक्ति

विधानसभा में आज राज्य में डीएपी खाद की कमी, अमानक एवं काला बाजारी को लेकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार को घेरा। कृषि मंत्री रामविचार नेतम के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष के सदस्यों ने जमकर हंगामा एवं नारेबाजी की। विधानसभा की कार्रवाई दो बार स्थगित की गई। विपक्ष के सदस्य गर्भगृह में आकर धरना देने लगे। इसके पश्चात अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह उन्हें समझाइश दी कि वे स्वयं निलंबित हो गये है इसलिए सदन छोड़कर चले जाए। लेकिन विपक्ष के सदस्य नहीं माने और धरने पर बैठे रहे जिसके कारण विधानसभा की कार्रवाई फिर बाधित हुई। इसके पश्चात पुनः विधानसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई।

विधानसभा में आज कांग्रेस के उमेश पटेल ने डीएपी खाद की मांग तथा इसकी आपूर्ति के बारे में जानकारी मांगी। उन्होंने पूछा की सरकार किसानों को किस कारण से डीएपी खाद उपलब्ध नहीं करा पा रही है। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने बताया कि भारत सरकार द्वारा 3,10, 000 टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जून माह तक 2, 19 हजार मीटरिक टन की सप्लाई उर्वरक मंत्रालय द्वारा की गई है। मंत्रालय द्वारा 30 जून 2025 तक 108000 टन का भंडारण किया गया है। उन्होंने कहा कि सप्लाई निरंतर जारी है राज्य में खाद की कमी नहीं है वैकल्पिक खाद के रूप में नैनो डीएपी की पूर्ति की जा रही है।

अमानक खाद की आपूर्ति करने का आरोप लगाया भूपेश बघेल ने

प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि राजनांदगांव सहित अन्य जिलों में अमानक खाद बेची जा रही है। जिसके कारण किसान परेशान हो गये है। कृषि मंत्री ने कहा कि अमानक खाद का नमूना लिया गया है जिसकी जांच जारी है। उन्होंने बताया कि सहकारी समितियों के माध्यम से 60 प्रतिशत खाद की आपूर्ति की जा रही है शेष निजी क्षेत्रों को दी

जाती है। कांग्रेस के उमेश पटेल ने कहा कि खाद की काली बाजारी हो रही है यह 1900 प्रति बोरा की दर से मिल रही है। कृषि मंत्री ने कहा कि धड़ियाली आंसू बहाना बंद करे। कांग्रेस शासन काल में भी यह संकट बरकरार था।

अध्यक्ष ने कांग्रेस सदस्यों को दी समझाइश

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि इस पूरे मुद्दे पर 15 20 मिनट से अधिक चर्चा हो चुकी है। अन्य सदस्यों को भी प्रश्न पूछना है इसलिए कृषि मंत्री बताया कि डीएपी की शतप्रतिशत व्यवस्था के लिए आप क्या कर रहे हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि यह एक वैश्विक समस्या है सभी राज्यों में डीएपी को लेकर संकट चल रहा है। वैकल्पिक खाद के रूप में तरल नैनों डीएपी का उपयोग करने की सलाह दी गई है। सदन में देवेंद्र यादव, रामकुमार यादव, संगीता सिन्हा सहित अन्य सदस्यों ने भी खाद की समस्या को लेकर प्रश्न दागे।

किसान विरोधी सरकार नहीं चलेगी

सदन के अंदर विपक्षीय सदस्यों के आक्रामक रूप को देखते हुए विधानसभा की कार्रवाई पहले पांच मिनट के लिए स्थगित की गई। कृषि मंत्री के जवाब से असंतुष्ठ कांग्रेस सदस्यों ने जमकर नारेबाजी की। किसान विरोधी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मंत्री इस्तीफा दो इस्तीफा दो के नारे लगाए गये। विधानसभा में कांग्रेस के अनीला भेड़िया संगीता सिन्हा, कविता लहरे, यशोदा वर्मा, लाल जी राठिया एवं लखेश्वर बघेल ने भी बेंच में खड़े होकर अपना विरोध किया तथा नारा लगाते हुए गर्भ गृह में आ गये।

गर्भगृह में दिया धरना

कांग्रेस विधायकों ने आज नारेबाजी करते हुए धरना दिया तथा वहां पर बैठ गये। विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह कहा कि विस की प्रक्रिया के अनुसार वे स्वयं निलंबित हो गये है छग विस उच्च संसदीय परंपरा के लिए जाने जाती है इसलिए आप इसकी गरीमा का ध्यान रखें। लेकिन विपक्ष सदस्य नहीं माने और नारे बाजी करते रहे। जिसके कारण विस की कार्रवाई एक बार पुनः स्थगित हुई इसके पश्चात 12.40 को प्रारंभ हुई।

नक्सलियों को आश्रय देने और सहयोग करने वाला आरोपी गिरफ्तार

कांकेर, कांकेर पुलिस ने नक्सलियों को आश्रय देने और सहयोग करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने नक्सलियों हेतु मुख्य सामग्री सप्लाई में अहम भूमिका थी। नक्सली कमांडर प्रसाद व कुंयेमारी-किसकोड़ो एरिया कमेटी के अन्य नक्सलियों के साथ लगातार संपर्क में रहकर हत्या के प्रयास जैसे घटनाओं को अंजाम देने में सहयोग किया था। उमनि एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कांकेर आई. के. एलिसेला (भापुसे) के निर्देशन पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कांकेर दिनेश कुमार सिन्हा (रापुसे) के पर्यवेक्षण तथा डीएसपी नक्सल ऑपरेशन गिरिजाशंकर साव (रापुसे), डीएसपी डीआरजी अविनाश ठाकुर (रापुसे) व डीएसपी प्रतिभा लहरे के नेतृत्व मे थाना आमाबेड़ा के अपराध 16/2022 धारा 147, 148, 149, 307 भादवि. 25, 27, आर्म्स एक्ट 23, 38(2), 39(2), 17, 18-।, 19 विधि विरूद्ध क्रिया कलाप निवारण अधिनियम के मामले में प्रतिबंधित भाकपा माओवादी संगठन के उत्तर बस्तर डिवीजन के कुंयेमारी-किसकोड़ो एरिया कमेटी के बड़े कैडर के नक्सलियों को अपने घर में छिपाकर रूकवाकर आश्रय देने, अपने साथियों के साथ नक्सली शहीद सप्ताह मीटिंग व जन अदालत के आयोजन करने और नक्सलियों के लिए सामग्री सप्लाई करने वाला नक्सली सहयोगी आरोपी रमेश कुमार मंडावी पिता रजमन मंडावी उम्र 35 वर्ष निवासी कोकवार ग्राम अर्रा थाना आमाबेडा जिला-उ.ब. कांकेर को दिनांक 16.07.2025 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय से न्यायिक रिमांड प्राप्त कर जेल भेजा गया।

दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी एवं कपास की फसल लेने वालों को भी मिलेगा कृषक उन्नति योजना का लाभ

0 प्रति एकड़ दस हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी

0 कृषि विभाग ने जारी किए विस्तृत दिशा-निर्देश

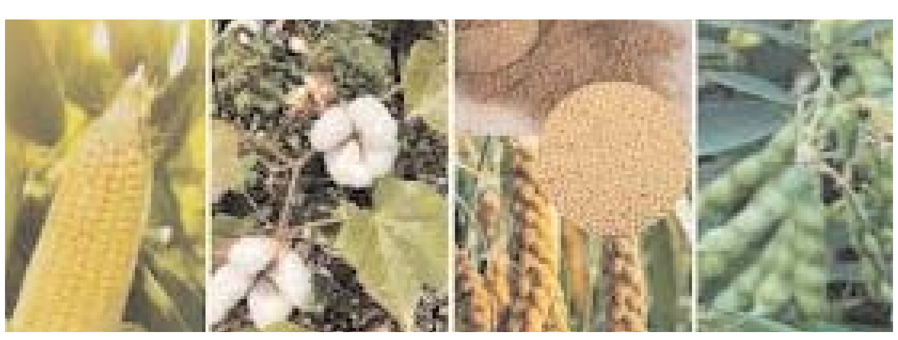

रायपुर, राज्य सरकार की कृषक उन्नति योजना का फायदा धान के अलावा दलहन, तिलहन, मक्का, लघु धान्य फसल, कोदो, कुटकी, रागी एवं कपास की फसल लेने वाले किसानों को भी मिलेगा। उन्हें प्रति एकड़ दस हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। राज्य शासन के कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग ने योजना के क्रियान्वयन के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

कृषि विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य का अधिकांश क्षेत्र वर्षा आधारित होने से मौसमीय प्रतिकूलता एवं कृषि आदान लागत में वृद्धि के कारण कृषि आय में अनिश्चितता बनी रहती है। इनके कारण किसान फसल उत्पादन के लिए आवश्यक आदान जैसे उन्नत बीज, उर्वरक, कीटनाशक, यांत्रिकीकरण एवं नवीन कृषि तकनीकी में पर्याप्त निवेश नहीं कर पाते हैं। राज्य सरकार द्वारा कृषि में पर्याप्त निवेश एवं काश्त लागत में राहत देने के लिए कृषक उन्नति योजना प्रारंभ की गई गई है। राज्य शासन ने फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन देने, दलहन व तिलहन फसलों के क्षेत्र विस्तार तथा इनके उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य के साथ चिन्हित अन्य फसलों पर आदान सहायता राशि देने का निर्णय लिया है।

कृषक उन्नति योजना का लाभ केवल उन्ही कृषकों को मिलेगा जिन्होने एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीयन कराया है। विगत खरीफ मौसम में एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीकृत ऐसे कृषक जिन्होंने धान की फसल ली है तथा प्रदेश की सहकारी समितियों में समर्थन मूल्य पर धान विक्रय किया है, ऐसे किसानों द्वारा धान के स्थान पर अन्य खरीफ फसल के लिए किसान पोर्टल में पंजीयन तथा गिरदावरी में रकबे की पुष्टि के उपरांत मान्य रकबे पर 11 हजार रुपए प्रति एकड़ की दर से आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी। खरीफ मौसम में दलहन, तिलहन, मक्का, लघु धान्य फसल, कोदो, कुटकी, रागी एवं कपास उगाने वाले किसानों को एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीयन तथा गिरदावरी में रकबे की पुष्टि उपरान्त मान्य रकबे पर दस हजार रुपए प्रति एकड़ की दर से आदान सहायता प्रदान की जाएगी। कृषक उन्नति योजना के नवीन दिशा-निर्देशों के अनुसार विधिक व्यक्तियों जैसे ट्रस्ट, मण्डल, प्राइवेट लिमिटेड, समिति, केन्द्र एवं राज्य शासन की संस्था, महाविद्यालय आदि संस्थाओं को योजना से लाभ लेने की पात्रता नहीं होगी। जो कृषक प्रमाणित धान बीज उत्पादन कार्यक्रम लेते हैं, और सामान्य धान भी सहकारी समितियों में विक्रय करते है, उनके द्वारा कुल विक्रय की जाने वाली धान की मात्रा, उनके कुल धारित रकबे की सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए। इसे छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित एवं छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड द्वारा आपसी समन्वय से सुनिश्चित किया जाएगा। कृषकों को आदान सहायता राशि का भुगतान कृषि भूमि सीलिंग कानून के प्रावधानों के अध्याधीन किया जाएगा। कृषकों को आदान सहायता राशि उनके बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से की जाएगी।

केन्द्र और राज्य शासन में जनल्याणकारी योजनाओं को आपसी समन्वय के साथ धरातल पर पहुंचाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है -सांसद महेश कश्यप

विपरीत परिस्थिति और चुनौतियों के बावजूद बीजापुर जिला प्रशासन का कार्य सराहनीय है

बस्तर सांसद महेश कश्यप की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक सम्पन्न

बीजापुर, लोकशक्ति । बीजापुर जिला कार्यालय के इन्द्रावती सभाकक्ष में बस्तर सांसद श्री महेश कश्यप की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक सम्पन्न हुई। सांसद श्री महेश कश्यप ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना को साकार करने, माननीय गृहमंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में मार्च 2026 तक बस्तर पूरी तरह से नक्सलमुक्त हो जाएगा।

अतः केन्द्र सरकार एवं छत्तीसगढ़ माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य शासन की अनेको महत्वाकांक्षी योजनाएं संचालित है। अतः केन्द्र और राज्य शासन के जनकल्याणकारी योजनाओं का धरातल पर शतप्रतिशत क्रियान्वयन जरूरी है। बीजापुर जिला में विपरीत परिस्थिति और कठिन चुनौतियों के बावजूद जिला प्रशासन जमीनी स्तर पर बेहतर कार्य कर रही है। हमारे जांबाज जवानों ने सुरक्षा व्यवस्था को अपने हाथों में लिए हैं, जिससे जिला प्रशासन अब पूरी मुस्तैदी के साथ योजनाओं को पहुंचा रही है। हमें और भी बेहतर समन्वय के साथ पूरे समर्पण के भाव से योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है ताकि आदिवासी बाहुल्य बीजापुर जिला में निरंतर विकास की गति बढ़ते रहे।

कभी माओवादी के आतंक के रूप में जानने वाला जिला अब शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सड़क, बिजली, पानी, कनेक्टिविटी सहित मूलभूत सुविधाओं के लिए मशहूर हो रहा है। बस्तर क्षेत्र में पर्यटन को भी बढ़वा मिल रहा है। जिससे विश्व पटल पर अब पर्यटन के लिए उभरते नजर आ रहा है। माओवाद के समूल खात्मे के बाद विकास की गति और तेज होगी। जिससे शासन-प्रशासन को और कड़ी मेहनत लगन और समर्पण के साथ पूरी ऊर्जा के साथ विकास के कार्यो में अपनी सहभागिता देनी होगी।

बैठक में कलेक्टर श्री संबित मिश्रा ने जिले के समग्र विकास हेतु संचालित योजनाओं एवं उनके क्रियान्वयन तथा योजनाओं के क्रियान्वयन मे आने वाली चुनौतियों को भी बताया। जिला प्रशासन के विभागीय अधिकारियों ने अपने-अपने विभाग के योजनाओं की प्रगति संबंधी जानकारी पीपीटी के माध्यम से प्रस्तुत किए। जिसमें प्रधानमंत्री आवास, नरेगा, राष्ट्रीय आजिविका मिशन, स्वच्छ भारत शहरी एवं ग्रामीण, प्रधानमंत्री सड़क योजना, राष्ट्रीय समाजिक, सहायता कार्यक्रम, जल जीवन मिशन, क्रेडा, प्रधानमंत्री कृषि, सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय भूअभिलेख आधुनिकीकरण राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सर्व शिक्षा अभियान।

जिले में 01 जून से अब तक 5224.1 मिमी वर्षा

जशपुरनगर (आरएनएस)। जशपुर जिले में 01 जून से अब तक 5224.1 मिमी वर्षा हो चुकी है। जिले में बीते 10 वर्षों की तुलना में 17 जुलाई तक की स्थिति में 3457.6 मिमी औसत वर्षा हुई है। बीते दिवस जिले में 38.2 मिमी वर्षा हुई है।

भू-अभिलेख शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार 01 जून से अब तक तहसील जशपुर में 552.3 मिमी, मनोरा में 669.2 मिमी, कुनकुरी में 729.6 मिमी, दुलदुला में 356.0 मिमी, फरसाबहार में 445.6 मिमी, बगीचा में 533.8 मिमी, कांसाबेल में 533.8 मिमी, पत्थलगांव में 419.0 मिमी, सन्ना में 608.6 मिमी एवं बागबहार में 376.2 मिमी वर्षा हो चुकी है। सर्वाधिक वर्षा कुनकुरी में दर्ज की गई है।

प्राकृतिक आपदा में जनहानि के एक मामले में प्रभावित परिजन के लिए 4 लाख की राशि स्वीकृत

जशपुरनगर कलेक्टर रोहित व्यास ने प्राकृतिक आपदा में जनहानि के एक मामले में प्रभावित परिजन को आर.बी.सी. 6-4 के तहत् 04 लाख रुपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि की स्वीकृत दी है। फरसाबहार तहसील अंतर्गत ग्राम तपकरा निवासी स्व. स्वर्ण तिग्गा का मधुमक्खी के काटने से 29 सितम्बर 2024 को मृत्यु हो गई। मृतक के निकटतम वारिस उनके भाई अनिल तिग्गा हेतु 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।

अग्निवीर वायु सेना में भर्ती के लिए ऑनलाईन आवेदन 31 तक आमंत्रित

जशपुरनगर (आरएनएस)। भारतीय वायु सेना भर्ती कार्यालय भोपाल द्वारा म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ के अविवाहित महिला एवं पुरूष आवेदकों से अग्निवीर वायु वर्ष 2026 हेतु ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये गये है। आवेदन वेबसाईट www.agnipathvayu.cdac.in पर 11 जुलाई 2025 से 31 जुलाई 2025 रात्रि 11.00 बजे तक किये जा सकते हैं। जिला रोजगार अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार अग्निवीर वायु में आवेदन करने हेतु आवेदक के लिए योग्यता निर्धारित की गई है। जिसमे तहत् आवेदक का जन्म 02 जूलाई 2005 से 02 जनवरी 2009 के बीच हुआ होना होगा और जो 10 + 2 या समकक्ष विज्ञान समुह फिजिक्स, मैथ्स, और अग्रेंजी में किसी मान्यता प्राप्त केन्द्रीय या राज्य या केन्द्र शासित बोर्ड से न्युनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ जिसमें अग्रेंजी विषय में 50 प्रतिशत अंक हो व 12 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाईल, कम्प्यूटर साईस, इन्स्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, इन्फर्मेशन टेक्नोलॉजी मान्यता प्राप्त बोर्ड राज्य अथवा केन्द्र शासित से 50 प्रतिशत अंकों के साथ।

मुख्यमंत्री ने बीजापुर के युवा ग्रेजुएट पंच का बढ़ाया हौसला

बस्तर का हर गांव बनेगा आपका अच्छा गांव - मुख्यमंत्री

बीजापुर जिले के युवाओं से मुख्यमंत्री ने की आत्मीय मुलाकात

रायपुर,

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज यहां छत्तीसगढ़ विधानसभा परिसर में स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना के तहत राजधानी रायपुर के भ्रमण पर आए बीजापुर जिले युवाओं से मुलाकात की। मुख्यमंत्री श्री साय इन युवाओं से बहुत आत्मीयता से मिले और उनसे राजधानी रायपुर भ्रमण के अनुभवों को जाना। मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर का हर गांव आपका अच्छा गांव बनेगा। बस्तर के विकास को अब कोई नहीं रोक सकता। बस्तर का युवा आज आत्मविश्वास से भरा है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने बीजापुर जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों से आये युवाओं से उनका हाल-चाल जाना और आत्मीय चर्चा की। मुख्यमंत्री ने युवाओं से पूछा कि वे विगत डेढ़ वर्षों में क्या परिवर्तन महसूस कर रहे हैं ? युवाओं ने बताया कि बहुत परिवर्तन है। अब हमारे क्षेत्र में सड़कें बन रही हैं, बिजली की व्यवस्था हुई है और आंगनबाड़ी केंद्र भी खुल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर का विकास हमारी सरकार की प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने युवाओं से उनकी पढ़ाई-लिखाई और गतिविधियों के विषय में जानकारी ली। बीजापुर के एक युवा ने मुख्यमंत्री श्री साय को बताया कि वह जूलॉजी विषय से बीएससी कर चुका है और वर्तमान में वह अपने गांव का पंच है। उसका एक साथी भी पंच निर्वाचित हुआ है। मुख्यमंत्री ने इन युवाओं के जज्बे की सराहना की और उनका हौसला बढ़ाया।

इस दौरान उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने बच्चों से पूछा- कितने बच्चे इंस्टाग्राम चलाते हैं? जब इस प्रश्न पर कई बच्चों ने हाथ उठाया तो मुख्यमंत्री ने आश्चर्यमिश्रित मुस्कान के साथ कहा- अब बस्तर के हमारे बच्चे भी समय के साथ हाईटेक हो रहे हैं। ये सुनकर ठहाके गूंज उठे। मुख्यमंत्री ने इस बात पर खुशी जाहिर की कि युवा अपडेट हैं और तकनीक को समझ रहे हैं। युवाओं ने बताया कि उनके गांव में अब मोबाइल टावर भी लग रहे हैं।

युवाओं ने मुख्यमंत्री को बताया कि वे कल राजधानी रायपुर आये हैं। उन्होंने मुक्तांगन, जंगल सफारी सहित अन्य जगहें देखी हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने युवाओं से कहा कि वे राजधानी रायपुर के भ्रमण के अनुभव का पूरा लाभ उठाएं।

स्वामी,मुद्रक,प्रकाशक प्रेमेन्द्र अग्रवाल द्वारा अस्मा पब्लिशर्सस इण्डिया प्राईवेट लि.,जयस्तंभ चौक, रायपुर से मुद्रित कर तथा 5/756 रामसागरपारा, सिंधी स्कूल के पीछे, स्टेशनरी हाऊस, रायपुर 492001 (छ.ग.) से प्रकाशित। **संपादक प्रेमेन्द्र अग्रवाल ।**
www.lokshakti.in, lokshaktidaily@gmail.com, twitter.com/lokshaktidaily, facebook.com/lokshaktidaily **कार्यकारी संपादक : राजेश अग्रवाल** (किसी भी विवाद पर न्यायालय क्षेत्र रायपुर होगा)